सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

सु-विचार
" रफ्तार कम हो चलेगा
पर दिशा सही होनी चाहिए "...!!
अज्ञात...

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष-01 अंक-76 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, सोमवार 06 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए,

कांग्रेस नक्सलवादियों को हमेशा दी है बढ़ावा-अशोक चौधरी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नक्सलवादियों को हमेशा से कांग्रेस ही प्रमोट कर रही है और इसका बीजारोपण 1947में आजादी के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रोग्राम बनाया था। इसमें नेहरू जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सही बात यह भी है कि नेहरू जी को नक्सलवाद के बाद के भारत की कोई सोच भी नहीं था। लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने कम्युनिस्टों की मन्सा पर पानी फेर दिया, कम्युनिस्टों ने बहुत हाथ पैर मारा लेकिन सरदार पटेल तो आखिर सरदार पटेल हैं वह दूर दृष्टि भी रखते थे और सख्त प्रशासक भी थे उन्होंने नक्सलवादियों के प्रमोशन को जड़ से ही समाप्त कर दिया। लेकिन नेहरू जी एवं स्व. लाल बहादूर शास्त्री के बाद जब कांग्रेस में दो फाड़ हो गया तो इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट से समझौता किया इस समय नक्सलवाद प्रारंभ किया गया।

यह 1967 की बात है श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता चाहिए था और कम्युनिस्टों को अपने विचारधारा मजबूत करनी थी। दोनों अंधे और लंगड़ों की दोस्ती-यारी खूब फली फूली। इतिहास गवाह है कि चुनाव जीतने के लिए भी कांग्रेस और वामपंथियों ने नक्सलवादियों का समर्थन प्राप्त किया कांग्रेस और वामपंथियों ने अपने दल को आगे रखा और राष्ट्र को पीछे रखा। लेकिन जब राष्ट्रवादी भाजपा जिसका उद्देश्य राष्ट्र प्रथम दल बाद में का शासन आया तब नक्सलवादियों को खत्म करने का कार्यक्रम बनाया और 2 साल पहले 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म करने का तारीख निश्चित करके सुरक्षा बलों को छूट दी गई और शासन ने मदद किया तो आज हम छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत को नक्सली मुक्त बनाने में सफलता हासिल किए हैं।

अब इक्के-दुक्के नक्सली अपने गुफा में छुपे हुए अपनी जान की खैर मना रहे हैं जिससे कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगी है, जिससे उनमें खलबली मच गई है उन्हें यह हैरानी भी हो रही है कि भाजपा ने जो कहा वह समय सीमा में कर दिखाया। छत्तीसगढ़ का विकास और भारत के नक्सली से पीड़ित अन्य राज्य भी अब तेजी से विकास कर पाएंगे जिससे कांग्रेसियों और वामपंथियों के सीने में सांप लोट रहा है। अशोक चौधरी ने कहा जिस तरह से वामपंथी मुक्त भारत हो गया है इस तरह कांग्रेस मुक्त भारत भी जल्दी ही बनेगा क्योंकि इन्होंने देश के साथ छल किया है, जनता सब समझ चुकी है इनका खात्मा निश्चित है।

टीएमसी पर जमकर बरसे पीएम मोदी

मोदी ने दावा किया बंगाल में चल रही है परिवर्तन की लहर, चुनाव के बाद होगा टीएमसी का हिसाब

नई दृष्टिबिंदु / कूचबिहार

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठियों को बाहर करेंगे. बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रही है. उन्होंने कहा कि एक ओर सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है. टीएमसी की करप्शन कंपनी भयभीत है. उन्होंने कहा कि कूच बिहार में आज की रैली जमीनी हकीकत और लोगों के मिजाज को साफ तौर पर दर्शाती है. पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार, हिंसा और शासन-व्यवस्था के चरमराने को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी. ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, जनसैलाब और वो उत्साह, जनता का जूनून तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूचबिहार ने उस पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कूचबिहार में भारी संख्या में लोगों ने यह साफ कर दिया है कि टीएमसी का समय खत्म हो गया है ! पूरे बंगाल में तपलटानो दोरकार चाई भाजपा सरकार की गूंज है !

पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर टीएमसी का भय है, और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक ओर टीएमसी के विजानिकटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है. एक ओर घुसपैठ कराकर, विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर संदेशखाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारीशक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है. मैं आपको

भरोसा देता हूं कि इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा. चुन-चुन कर हिसाब किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा. चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो इस बार न्याय होकर रहेगा. यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती. दो-तीन पहले पूरे देश ने देखा है कि कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने कहा कि हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है. मैं यहां आए सभी बहनों बेटियों को, बंगाल की हर बहन-बेटियों से कहूंगा कि बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है।

हाईकोट के आदेश के बाद शुभा दामोदर मिश्रा फिर होंगे गौरेला के सीईओ, कलेक्टर को नहीं है हटाने का अधिकार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कलेक्टर की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा तय करते हुए कहा है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। अदालत ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पार्थ प्रतिम साहू ने की।

मामला बिलासपुर के निवासी शुभा दामोदर मिश्रा से जुड़ा है। उन्हें 18 जून 2025 को सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा जनपद पंचायत गौरेला (जिला जीपीएम) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद पर पदस्थ किया गया था। वे जून 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं। इसी दौरान 11 मार्च 2026 को कलेक्टर, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही ने आदेश जारी कर उन्हें सीईओ के प्रभार से हटाते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गौरेला के कार्यालय में पदस्थ कर दिया।

इस आदेश के खिलाफ शुभा मिश्रा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋतभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि 11 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, शासन द्वारा नियुक्त किसी भी जनपद पंचायत सीईओ को हटाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होती है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला के पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस का हिमंता और उनकी पत्नी पर हमला, सीएम ने दी मानहानि की धमकी

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

असम में विधानसभा चुनाव से पहले नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं। इस आरोप पर बीजेपी नेता की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी।

यह विवाद पवन खेड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसने पता चलता है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। पहला यूएई का गोल्डन कार्ड है, दूसरा एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट है और तीसरा मिस का पासपोर्ट है। इनमें से दी पासपोर्ट इस्लामिक देशों के हैं, फिर भी वे सार्वजनिक रूप से अपने धार्मिक जुड़ाव का दावा करते रहते हैं।

खेड़ा ने कहा आप मुख्यमंत्री हिमंत और उनकी पत्नी की तस्वीरें देख रहे हैं। उनके नाम जमीन हड़पने, मंदिर के पैसे का दुरुपयोग करने, सरकारी सब्सिडी में हेराफेरी करने और चिट फंड घोटालों जैसे कई आरोपों से जुड़े रहे हैं। लेकिन आज, हम जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, उनका सीधा संबंध भारत के बाहर के मामलों से है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा इन दावों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह और उनकी पत्नी, 48 घंटों के भीतर खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा पवन खेड़ा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासित जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके कमजोर होते जनाधार को ही उजागर करते हैं।

सीएम हिमंत ने कहा कि मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मामले दर्ज कराएंगें। उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक बार जब अदालत में सच्चाई साबित हो जाएगी, तो पवन खेड़ा के अपने कामों के लिए नतीजों का सामना करना पड़ेगा और कानून अपना काम करेगा। मुझे विश्वास है कि पवन खेड़ा का झूठ का अभियान अब अपने अंत के करीब है। आखिरकार खेड़ा जेल जाएंगे।

पाइप लाइन लीकेज से जलभराव की समस्या का किया समाधान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर जोन-2 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 के सुपेला बाजार क्षेत्र में जल आपूर्ति पाइप लाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक बड़ा लीकेज होने से इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई।

प्राप्त सूचना के अनुसार सुपेला रावण भाटा, शीतला तालाब के समीप एवं हाडर्वेयर लाइन क्षेत्र में पाइप लाइन से भारी मात्रा में पानी बहने लगा। एक ही समय में अत्यधिक पानी नालियों में जाने से लक्ष्मी नगर के पास शीतला तालाब मार्ग की पुलिया जाम हो गई। पुलिया में पेयजल की तीन बड़ी पाइप लाइनें गुजरती हैं, जिनमें प्लास्टिक झिल्ली और कचरा फंस जाने से पानी का बहाव रुक गया। इसके चलते सड़क पर पानी जमा हो गया और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जलभराव की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम भिलाई की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने बांस की सहायता से जाम पुलिया को खोला और उसमें फंसे कचरे बाहर निकाले। इसके बाद जल निकासी की व्यवस्था सुचारु की गई। साथ ही सड़क पर फैले कीचड़ और कचरे को साफ कर संक्रमण से बचाव के लिए चूना पाउडर का छिड़काव भी किया गया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो।

अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पर राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

5 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात बरामद

पिछले महीने 14 मार्च को प्रार्थिया जीवन-ए कॉलोनी, राजनांदगांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि लगभग 3 बजे अज्ञात 3 से 4 व्यक्ति उसके मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और आरोपियों ने डरा, धमका कर आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 127/26 धारा 331(4), 305, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वहीं लक्ष्मीनगर निवासी प्रार्थी की मोटर सायकल ड्रीम योगा चोरी होने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 128/26 धारा 303(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया तथा लक्ष्मीनगर बी कॉलोनी निवासी एक अन्य प्रार्थी की रिपोर्ट पर घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने के संबंध में अपराध क्रमांक 130/26 धारा 331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार एवं निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

टीम द्वारा घटना स्थल से लेकर राजनांदगांव शहर के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान आरोपियों के दुर्ग की ओर जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके पश्चात दुर्ग-भिलाई, रायपुर एवं बिलासपुर के सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों के हैदराबाद में होने की पुष्टि हुई।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश पर साइबर सेल एवं थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम हैदराबाद रवाना की गई, जहां दो दिन तक सतत प्रयास के बाद संदेही आरोपियों की पहचान कर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने राजनांदगांव के जीवन आवास कॉलोनी में एक ही रात में तीन स्थानों पर चोरी की घटनाएं कारित की थीं। घटना के बाद आरोपी दुर्ग-भिलाई होते हुए ट्रेन से बिलासपुर पहुंचे, जहां अगले दिन सरकंडा थाना एवं मोपका चौकी क्षेत्र में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया और पुनः ट्रेन से हैदराबाद भाग गए।

आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान में 2 नग चांदी का दिया, 1 बड़ा एवं 01 छोटा चांदी का कटोरा, 6 नग चांदी की बिछिया, 5 नग चांदी की बिछिया, 7 जोड़ी चांदी के कान के टॉप्स, 4 नग चांदी के कान के टॉप्स, 2 नग चांदी का कड़ा, चांदी एवं काले मोती का बाजूबंद, 1 नग चांदी का छोटा लड्डू, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स, 2 जोड़ी सोने के लॉकेट शामिल है। कुल बरामद संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रुपये है। घटना में शामिल चाकू को भी आरोपियों से जब्त किया गया है। घटना में शामिल अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धारा 111, 112 व 310 बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हैदराबाद के शेट्टी गैंग द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में शशि कुमार पिता वासु कुमार, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सैलम तिलायम पट्टी, थाना सैलम, जिला सैलम (हैदराबाद), सेट्टी विजय पिता देवेंद्र कुमार, उम्र 45 वर्ष निवासी नामपल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र, थाना बंजारा हिल्स, हैदराबाद, सेट्टी सूर्या पिता विजय कुमार, उम्र 31 वर्ष निवासी गोड़ूपल आयतनगर, थाना रिंगरोड उप्पल नगर, जिला हैदराबाद शामिल हैं।

इस कार्रवाई में सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर, उपनिरीक्षक नरेश सर्वा,सउनि मनमोहन साहू, प्रधान आरक्षक जी. सीरिल,बसंत राव,धीरज डडसेना आरक्षक अविनाश झा, परिवेश वर्मा, पुनेश साहू, आदित्य ठाकुर,प्रश्यात जैन,हेमंत साहू, आशीष मानिकपुरी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

राजनांदगांव पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि वे घर छोड़कर बाहर जा रहे हों या लंबी अवधि के लिए घर खाली रहने वाला हो, तो इसकी सूचना अपने पड़ोसियों एवं नजदीकी पुलिस थाना को अवश्य दें, ताकि क्षेत्र में प्रभावी निगरानी रखी जा सके और चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथों में होती है-शिक्षा मंत्री यादव

स्कूल शिक्षा मंत्री एफएलएन शिक्षक सम्मान समारोह में हुए शामिल, 100 उत्कृष्ट शिक्षक हुए सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव रविवार को खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित एफएलएन सह नवाचारी वारियर्स शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री यादव ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एफएलएन (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बन सकें।

उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होगी, बच्चा उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथ में होती है, इसलिए स्कूलों में नए शिक्षण तरीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा को अपनाया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने एफएलएन के तहत शिक्षकों के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही शिक्षा में नवाचार कर विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने वाले 100 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

समारोह में बस्तर के 10, बिलासपुर के 30, दुर्ग के 26, रायपुर के 18 और सरगुजा के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एससीईआरटी के डायरेक्टर के कुमार, शिक्षा विभाग के पूर्व संचालक आशुतोष चावरे, डीईओ अरविंद मिश्रा, सुनील मिश्रा, एफएलएन प्रभारी शबनम खान, मंडल अध्यक्ष महेन्द्र लोढ़ा तथा कमलेश फेकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

शाबाश योजना 2025-26 के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ समापन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

केंद्रीय यांत्रिकी संगठन में विगत दिनों शाबाश योजना 2025-26 के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत संयंत्र द्वारा कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है।

कार्यक्रम में केंद्रीय यांत्रिकी संगठन के विभिन्न विभागों से कुल 07 कार्यपालक एवं 12 गैर कार्यपालक कर्मियों को शाबाश स्कीम (कैटेगरी-2) के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एस. के. बेहेरा एवं मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने सभी चयनित कर्मियों को पुरस्कार प्रदान कर

सम्मानित किया। पुरस्कृत में कर्मियों महाप्रबंधक (सी.एम.एम.) सुनील कुमार, उप महाप्रबंधक (मेक. सविर्सेस) संजेश, सहायक महाप्रबंधक (सी.एम.एम.) राजेश नायर, सहायक महाप्रबंधक (पी.ई.एम.) विजयकुमार सैनी, सहायक महाप्रबंधक अरविंदर सिंह चाना, प्रबंधक (प्लांट गैरेज) राकेश चौधरी, सीनियर ड्राफ्ट्समैन शिव प्रसाद, ओ.सी.टी. दीपक कुमार यादव, सहायक प्रबंधक आदित्य कुमार साहू सहित अन्य कर्मी शामिल रहे।

इस अवसर पर एस. के. बेहेरा एवं प्रमोद कुमार ने सभी पुरस्कृत कर्मियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्मियों की यही प्रतिबद्धता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन संयंत्र को वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने सभी कर्मियों को भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्टता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया। मुख्य महाप्रबंधक ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पुरस्कृत कर्मियों की भूमिका को विशेष रूप से सराहा तथा आगामी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया।

समारोह में महाप्रबंधक आशीष घोष, महाप्रबंधक नबर्षी राय, महाप्रबंधक वर्गीस पी. जॉन, महाप्रबंधक राकेश पाण्डे, महाप्रबंधक महाप्रबंधक महाप्रबंधक बी.एन. झा, आर.के. बोराह, मुजीब हुसैन, महाप्रबंधक मेजी मेजर सिंह, महाप्रबंधक प्रदीप्ता भौमिक, महाप्रबंधक राहुल निगम सहित केंद्रीय यांत्रिकी संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित अधिकारियों ने पुरस्कृत कर्मियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेल के स्वदेशी स्पेशल स्टील से आईएनएस तारागिरी को मिली मजबूती

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने नीलगिरी श्रेणी के चौथे स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस युद्धपोत को 03 अप्रैल, 2026 को नौसेना में शामिल किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसमें सेल द्वारा आपूर्ति किए गए लगभग 4,000 टन विशेष ग्रेड के स्टील प्लेटों की पूरी जरूरत का उपयोग किया गया है। इस विशेष इस्पात का उत्पादन सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों में किया गया है, जो कंपनी की उन्नत धातुकर्म क्षमताओं और निरंतर गुणवत्ता मानकों को प्रदर्शित करता है। सेल भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' मिशन को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है।

खास खबर

ग्राम तिरगा में श्रद्धापूर्वक मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ग्राम तिरगा में महान वीर योद्धा एवं राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दिल्लीवार कुर्मी समाज के पदाधिकारी एवं ग्राम प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों एवं वीरता को याद किया। वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज के उत्थान एवं राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय बेलचंदन, सर्किल युवा अध्यक्ष दधिश देशमुख, प्रधान गैंदलाल, उप प्रधान रामसाय बेलचंदन, शिवाजी स्मारक अध्यक्ष युवराज देशमुख, अघनू देशमुख, भरतलाल बेलचंदन, दयाराम दिल्लीवार, भूपेंद्र बेलचंदन, रामसिंग देशमुख, नंदलाल देशमुख, टेमन देशमुख, प्रवीण देशमुख, भुलऊराम देशमुख, नरेंद्र देशमुख, भीष्म देशमुख, उपसरपंच सूखिताराम ढीमर, दिलेश्वर यादव, संतु ठाकुर, बिरेंद्र कोतवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी के द्वारा शिवाजी महाराज के बताए मार्ग पर चलने के संकल्प के साथ किया गया।

राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली को प्रणाम कर लौटे डॉ. महेशचंद्र शर्मा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इस्पात नगरी भिलाई के साहित्य - संस्कृति के आचार्य डॉ. महेशचन्द्र शर्मा ने विगत दिनों प्रवास के दौरान भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि पंडित माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में उनकी प्रतिमा के दर्शन किए। मध्यप्रदेश के नमर्दापुरम् (होशंगाबाद) के पास बाबई नाम का क़स्बा है जो "माखन नगर" कहलाता है। डॉ.शर्मा ने बताया कि यहां पहुंचने पर विशेष प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव हुआ।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रभक्त कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार पं. माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध देशभक्ति पूर्ण और कालजयी कविता "पुष्प की अभिलाषा - चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं..." की रचना का अभी शताब्दी वर्ष हुआ है। पंडित चतुर्वेदी ने पांच जुलाई 1921 को बिलासपुर जेल में इसकी रचना की थी। वे असहयोग आन्दोलन के कारण बिलासपुर जेल में थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसे "प्रताप" में प्रकाशित किया। आचार्य डॉ.शर्मा ने माखन नगर से लौटने पर बताया कि उक्त कविता का जन्म बिलासपुर में हुआ अतः छत्तीसगढ़ को गौरव और गर्व का अनुभव होना स्वाभाविक है। वैसे तो कविता पूरे राष्ट्र की है परन्तु छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को विशेष रूप से जोड़ती है।

एक भारतीय आत्मा पंडित माखन लाल चतुर्वेदी कर्मवीर और प्रताप जैसे समाचार पत्रों के प्रसिद्ध सम्पादक भी थे। ऐसे ही मनीषी देशभक्त साहित्यकारों और पत्रकारों ने देश की बड़ी सेवा की। लोकमान्य पंडित बालगंगाधर तिलक और राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी आदि को भी इस सन्दर्भ में आदर्श और प्रेरक माना गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने "जवानी" और "जलियांवाला की बन्दी" आदि अन्य देशभक्ति पूर्ण कविताओं की रचना की थी। निश्चित रूप से साहित्यिक पत्रकारिता लोगों को राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण से जोड़ती है।

विश्व शांति के लिए आर्य समाज का राष्ट्रीय आह्वान : देशभर में किए यज्ञ और प्रार्थनाएं

वैश्विक तनाव के बीच 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश, छत्तीसगढ़ के 99 आर्य समाजों में विशेष आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

विश्व में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और वैश्विक तनाव के बीच, आर्य समाज द्वारा शांति और मानवता के संदेश को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सावर्देशिक दिल्ली मुख्यालय के आह्वान पर देशभर के आर्य समाजों में विश्व शांति के लिए यज्ञ एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया।

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के 99 आर्य समाजों में भी विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गईं। सेक्टर-6 स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आचार्य अंकित शर्मा ने वैदिक मंत्रों एवं शांति मंत्रों का उच्चारण करते हुए समस्त विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य डॉ. अजय आर्य ने कहा कि वतर्मान समय में विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों का भय पूरे मानव समाज को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह दौर हमें ह्लवसुधैव कुटुम्बकम्ह्न का वास्तविक अर्थ समझा रहा है, जिसका संदेश भारत सदैव विश्व को देता आया है। मध्य पूर्व क्षेत्र एवं हॉरमुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न गतिरोध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे संपूर्ण विश्व चिंतित है।

उन्होंने शांति पाठ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वैदिक शांति मंत्र सम्पूर्ण सृष्टि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सागर और नदियों में शांति की कामना करता है। इसके पश्चात व्यक्ति स्वयं के लिए शांति की प्रार्थना करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्तिगत शांति तभी संभव है जब हमारे आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण हो। यही शांति का मूल सिद्धांत है।

आचार्य अजय आर्य ने उदाहरण देते हुए कहा कि शक्ति और पुरुषार्थ का महत्व अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भगवान हनुमान के माध्यम से समझाया कि वास्तविक शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुशासन, परिश्रम और साधना आवश्यक है। उन्होंने एक प्रेरक प्रसंग साझा करते हुए कहा कि केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि कर्म और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है।

उन्होंने महान समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को आज के समय में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके सिद्धांत ही विश्व में स्थायी शांति की स्थापना कर सकते हैं। स्वामी दयानंद ने छुआछूत और जन्म-आधारित जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए कर्म आधारित समाज की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के कर्म ही उसे सम्मान दिलाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कार्यक्रम में राजीव नागपाल, सुदर्शन गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, अवनी भूषण पुरंग, यतीन्द्र पुरंग, रवि आर्य, अरविंद मिश्रा, शुभ्रा नागपाल, प्रमिला सरपाल, सुनीता गुप्ता, मधु गुप्ता, ज्योति पुरंग, सोनिया पुरंग, कमलेश आर्य सहित अनेक श्रद्धालुओं ने विश्व शांति महायज्ञ में आहुति प्रदान की। आर्य समाज द्वारा आयोजित यह अभियान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि विश्व में शांति, एकता और मानवता के मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

दुर्ग ग्रामीण विधायक चंद्राकर ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अछोटी एवं ग्राम निकुम में विधायक ललित चंद्राकर ने 73.43 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की पूजा-अचर्ना से हुई। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधायक चंद्राकर ने कहा कि क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, स्वच्छता एवं सामुदायिक भवनों जैसे कार्यों से गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है और इनसे सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

ग्राम अछोटी में साहू पारा में 12 लाख की लागत से डोमशेड निर्माण, मंडी बोर्ड योजना के अंतर्गत 17.50 लाख की लागत से व्यावसायिक परिसर निर्माण तथा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 6.50 लाख से सतनाम भवन का निर्माण किया गया। इसके अलावा 5.20 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण, 1.50-1.50 लाख की लागत से बोर खनन एवं हैंडपंप स्थापना, 3.93 लाख से नाली निर्माण (भूमिपूजन) तथा 3.10 लाख से सड़क निर्माण कार्य किए गए।

ग्राम निकुम में 2.60 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया गया, वहीं 19.60 लाख की लागत से डोम शेड निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच झन्ना दिल्लीवार, जनपद सदस्य बेला यादव, उपसरपंच घनश्याम दिल्लीवार, मंडल अध्यक्ष लिकेश्वर देशमुख, महामंत्री पुराण देशमुख सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामवासियों की बड़ी भागीदारी रही।

शारदा सिन्हा के मरणोपरांत मृत शरीर चिकित्सा अध्ययन के लिए दान

दुर्ग। शरीर नश्वर है, लेकिन मानवता अमर है। इसी ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए दुर्ग के एलआईजी 450, पद्मनाभपुर निवासी 90 वर्षीय श्रीमती शारदा सिन्हा का मरणोपरांत देहदान संपन्न हुआ। उनके पार्थिव शरीर को चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों के अध्ययन हेतु अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जुनवानी, भिलाई को सौंपा गया। इस अवसर पर देहदान प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करने वालों में स्वर्गीय शारदा सिन्हा के परिजनों में राजेश श्रीवास्तव ,मधु श्रीवास्तव ,उमा वर्मा ,आशुतोष वर्मा के अलावा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपाटर्मेंट के एचओडी डॉ. अनिल रामभाऊ शिर्के, डॉ.राहुल गुलाटी, डॉ.प्रदनेश, डॉ.दिलीप कुमार, अजय सिंह राजपुत का विशेष योगदान रहा।

एनडीपीएस मामलों में साक्ष्य को सुदृढ़ बनाने दुर्ग पुलिस का विशेष प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में साक्ष्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 5 अप्रैल 2026 को पुरानी पुलिस लाइन स्थित दधीचि प्रशिक्षण हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें थाना स्तर के पुलिस बल को नारकोटिक्स ड्रग्स एवं प्रिक्यूरसर केमिकल डिटेक्शन किट के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान क्राइम सीन यूनिट, जिला दुर्ग की वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. स्मिता रानी भारदीय ने अफीम, गांजा, टैबलेट, ब्राउन शुगर, हेरोइन सहित विभिन्न मादक पदार्थों के वैज्ञानिक परीक्षण की विधियों को विस्तार से समझाया। साथ ही डिटेक्शन किट के प्रभावी उपयोग, साक्ष्य संरक्षण और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के तरीके बताए गए।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी से आए 35 प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण के उपरांत सभी थाना-चौकी को नारकोटिक्स ड्रग्स डिटेक्शन किट एवं प्रिक्यूरसर केमिकल डिटेक्शन किट वितरित किए गए, जिससे मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण कर साक्ष्य को और मजबूत किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में पुलिस लाइन दुर्ग के स्टाफ, डीसीआरबी शाखा एवं क्राइम सीन यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल मालिकों के चेहरों पर लौटी मुस्कान : दुर्ग पुलिस ने गुम मोबाइल लौटाए

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले में गुम हुए मोबाइल फोन वापस मिलने से मोबाइल मालिकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग ने विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2023 से 2026 तक गुम हुए 205 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। इन मोबाइलों का सत्यापन कर वास्तविक मालिकों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत एसीयू टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सतत प्रयासों के माध्यम से दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों से मोबाइल फोन खोज निकाले। इस पूरी कार्यवाही में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की अहम भूमिका रही।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की शपथ भी दिलाई गई और सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। इस सफलता में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, दुर्ग के निरीक्षक प्रमोद कुमार सरिया के नेतृत्व में टीम के अधिकारियों एवं संबंधित थाना स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए, तो तुरंत नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं और भारत सरकार के उएक्फ पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत अवश्य करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया पूरी करने से मोबाइल की खोज, ब्लॉकिंग और वैधानिक कार्रवाई में मदद मिलती है।

छग से कंचन सेंन्द्रे के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर समुदाय दिल्ली रवाना

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर बिल के विरोध में देशभर में ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच असंतोष व्याप्त है। इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट कंचन सेंन्द्रे के नेतृत्व में दुर्ग-भिलाई क्षेत्र से 20 सदस्यीय टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। यह टीम दिल्ली के जंतर-मंतर में आयोजित होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होगी।

इस टीम में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ समाज के अन्य सहयोगी व्यक्ति भी शामिल हैं, जो इस बिल के विभिन्न प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता और विरोध दर्ज कराने के लिए एकजुट हुए हैं। कंचन सेंन्द्रे ने रवाना होने से पूर्व बताया कि यह बिल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, आत्मसम्मान और स्वतंत्र पहचान के लिए कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की मांग है कि, सरकार इस बिल में आवश्यक संशोधन करे और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वास्तविक समस्याओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जंतर-मंतर में आयोजित प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे।

दिल्ली पहुंचने के बाद टीम ने जंतर-मंतर स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहां उपस्थित लोगों को इस बिल से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बिल समुदाय की स्वायत्तता और अधिकारों को सीमित कर सकता है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समुदाय के सदस्यों ने एक स्वर में सरकार से अपील की है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कानून में उचित बदलाव किए जाएं। यह प्रदर्शन न केवल विरोध का प्रतीक है, बल्कि यह ट्रांसजेंडर समुदाय की एकजुटता, जागरूकता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता को भी दर्शाता है।

ज्ञात हो कि वर्तमान केंद्र सरकार ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा के मौजूदा सत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) लिए संशोधन विधेयक पेश किया था। जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता को दर्शाया गया है। अर्थात अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा तत्पश्चात ही उन्हें व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। एक्टिविस्ट कंचन सेंन्द्रे के अनुसार सरकार द्वारा संशोधित विधेयक में बहुत सारी खामियां हैं।जिसे दूर करने हेतु सरकार के समक्ष मांग की जायेगी।और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पर पुर्नविचार अवश्य करेगी।

उद्योग मंत्री देवांगन ने रजत जयंती उद्यान को जनसेवा में किया समर्पित

वार्ड क्रमांक- 38 लालघाट चेकपोस्ट के नागरिकों को मिली सर्वसुविधायुक्त उद्यान की सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने रजत जयंती उद्यान को जनसेवा के लिए समर्पित किया। नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 38 लालघाट चेकपास्ट बस्ती के रहवासियों को आज एक सर्वसुविधायुक्त उद्यान की सौगात प्राप्त हुई है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, मेयर इन काउंसिल सदस्य हितानंद अग्रवाल, पार्षद नरेन्द्र देवांगन, पार्षद चेतन सिंह मैत्री, सत्येन्द्र दुबे, मुकुंद सिंह कंवर, मंगल बंदे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बालको जोनांतर्गत वार्ड क्र. 38 लालघाट के चेकपोस्ट बस्ती मुख्य मार्ग में 21 लाख 50 हजार रूपये की लागत से

सवर्सुविधायुक्त उद्यान का निर्माण कार्य कराया गया है, छत्तीसगढ़ गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 से मनाये जा रहे रजत जयंती समारोह के तहत उक्त उद्यान का नामकरण रजत जयंती उद्यान किया गया है।

इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुये प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 25 वर्ष पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उद्यान का नाम भी रजत जयंती उद्यान रखा गया, मुझे खुशी है कि आज यह सवर्सुविधायुक्त उद्यान जनताजनार्दन की सेवा के लिए समर्पित किया गया है।

उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमारी सरकार ने ही बनाया था और अब हमारी सरकार ही छत्तीसगढ़ को संवार रही है। 15 वर्षो तक डॉ. रमन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा प्रदेश का ऐतिहासिक रूप से विकास किया, अब उन्हीं की तर्ज

पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, यह हमारा सौभाग्य है कि जनताजनार्दन के आशीर्वाद से देश-प्रदेश व कोरबा मे ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा दर्जनों जनकल्याणकारी योजनायें संचालित कर गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सहित समाज के सभी वर्गो के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बनाये गये रजत जयंती उद्यान की यह सौगात लालघाट चेकपोस्ट बस्ती के नागरिक बंधुओं को प्राप्त हुई है। जिसके लिये मैं उन्हें हृदय से बधाई देती हूँ। उन्होने कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में कोरबा नगर निगम क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है, आमजनता की समस्याएं प्राथमिकता के साथ दूर की जा रही है, विगत 01 वर्ष के दौरान नगर निगम कोरबा ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है, बर्षो की समस्यायें दूर की गई है।

खास खबर

राज्यपाल ने पीएम जनमन अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया अवलोकन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम बेहराखार में पीएम जनमन योजना अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने यूनिट में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मोबाइल मेडिकल यूनिट में ऑक्सीजन सिलेंडर, सीवीसी मशीन, आवश्यक दवाइयों सहित विभिन्न उपचार उपकरण उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी तैनात रहती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

अवलोकन के उपरांत राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही अधिकारियों से कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में नियमित रूप से भ्रमण कर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन समुदायों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर पद्म जागेश्वर यादव, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस जात्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 13.22 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के ओड़गी और भैयाथान विकासखंड में 13.22 करोड़ रूपये से अधिक लागत के तीन अहम विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अचर्ना कर शुभारंभ किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विकासखंड ओड़गी के ग्राम हरिहरपुर (छतरंग रोड) में कागज नाला पर 419.37 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्रीमती राजवाड़े ने भैयाथान विकासखंड के ग्राम सांवरावा में 136.23 लाख रूपये की लागत से जलाशय जीणीद्धार कार्य का शुभारंभ किया । उन्होंने प्रतापपुरझ्रभैयाथान मुख्य मार्ग से परसापारा तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 766.37 लाख रूपये है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में सीधा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और भटगांव क्षेत्र विकास की नई दिशा में अग्रसर होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, पुल और जल संरचना का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में वन विकास निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राज्यपाल डेका ने मातृत्व वन में किया पौधरोपण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने सर्किट हाउस जशपुर के मातृत्व वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीता अशोक के पौधे का रोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार और वनमंडला अधिकारी शशि कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस मातृत्व वन में 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संवेदनाओं के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मातृत्व वन में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधरोपण किया गया है। इस पहल ने अभियान को भावनात्मक और सामाजिक रूप से विशेष महत्व प्रदान किया है।

राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती हैं और उनका स्थान सर्वोच्च होता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से हम माँ के प्रति सम्मान को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेगी।

उन्होंने कहा कि मातृत्व वन जैसी पहल न केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करेंगी।

मातृत्व वन के अंतर्गत पर्यावरणीय एवं औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का चयन कर उनका रोपण किया गया है। इनमें टिकोमा, झारुल, सीता अशोक, गुलमोहर, लक्ष्मीतरु, आंवला, बीजा, सिन्दूर, नागकेसरी, अर्जुन एवं जामुन जैसी प्रजातियाँ प्रमुख हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे, बल्कि आने वाले समय में औषधीय एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मातृत्व वन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, माताओं के प्रति सम्मान को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करना तथा नई पीढ़ी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। यह पहल ह्यहर घर एक पेड़, हर पेड़ में माँ की ममताह्न के संदेश को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

राज्यपाल ने केरेगांव होम-स्टे का किया अवलोकन

राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर प्रवास के दौरान शनिवार को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देशदेखा के समीप स्थित केरेगांव में विकसित होम-स्टे का अवलोकन किया। इस दौरान वे स्थानीय आदिवासी संस्कृति, जनजीवन और पारंपरिक आतिथ्य परंपरा से रूबरू हुए। होम-स्टे प्रवास के दौरान उन्होंने देशदेखा समूह की महिलाओं द्वारा पारंपरिक विधि से तैयार किए गए व्यंजनों का स्वाद चखा। राज्यपाल श्री डेका ने ग्रामीण परिवेश में विकसित होम-स्टे को प्रेरणादायक कदम बताया और कहा कि यह प्रयास न केवल ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय महिलाओं और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।

इस दौरान स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने 'जसक्राफ्ट' ब्रांड के तहत छिंद एवं कांसा से निर्मित पारंपरिक आभूषण माला एवं झुमके राज्यपाल को भेंट किए। राज्यपाल श्री डेका ने स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।

इस दौरान 'देशदेखा क्लाइंबिंग कम्पनी' के सदस्यों ने भी राज्यपाल से भेंट की। उन्होंने क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि यहां नियमित रूप से रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल ने अधिकारियों को ऐसे खेलों को निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन देने को कहा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक युवा इन गतिविधियों की ओर आकर्षित हों।

खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष 2025-26 में 16,625 करोड़ रुपए की प्राप्ति

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में पारदशिर्ता, तकनीकी नवाचार और सुदृढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।

खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त किया है, जो सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत निगरानी व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है।यह उपलब्धि न केवल प्रभावी प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है, बल्कि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है।

इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। यह वृद्धि राज्य शासन द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक और तकनीकी उपायों की सफलता को रेखांकित करती है।

खनिज राजस्व में इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में एनएमडीसी (NMDC) तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी

अनुकूलन शामिल है। इसके साथ ही, खनिज 2.0 जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदशिर्ता, निगरानी और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का विशेष ध्यान गौण खनिजों को भी खनिज 2.0 प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे संपूर्ण खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज परिवहन की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वीटीएस, आई-चेक गेट्स तथा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

राज्य की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत -मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में सतत वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

8 को माँ योग योगेश्वरी यती का रायपुर आगमन, 7 दिवसीय छग प्रवास पर रहेंगी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महामंडलेश्वर माँ योग योगेश्वरी यती 8 अप्रैल से 7 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर सनातन समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

डॉ. ओमप्रकाश देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णकालिक संघ प्रचारक विजय देवांगन भी उनके साथ रहेंगे। प्रवास के दौरान विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें वे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। माँ योग योगेश्वरी यती जी को सनातन परंपरा की साधिका, दिव्य हीलर और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। वे माँ काली की उपासक हैं और भगवान शिव की आराधना में समर्पित रही हैं। उनकी साधना में 12 वर्षो तक अखंड धूना, महामृत्युंजय मंत्र की हवन साधना, दीर्घ मौन व्रत और गंगा-यमुना तटों व हिमालय क्षेत्र में तपस्या शामिल रही है।

प्रवास के दौरान राजीव लोचन श्रीवास्तव के संयोजन में गौसेवा आयोग और योग आयोग के तत्वावधान में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद वे श्रीराम मंदिर में दर्शन-पूजन कर संध्या आरती में शामिल होंगी। साथ ही योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के निवास पर रात्रि भोजन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। 9 अप्रैल को वे बिलासपुर और अमरकंटक सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों के प्रवास पर रवाना होंगी। डॉ. देवांगन ने सनातन समाज के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर माँ के दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ लें।

राज्यपाल ने ग्राम बेहराखार जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदायों से की मुलाकात

बिरहोर समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, अधिकारियों को स्व-सहायता समूह बनाकर रोजगार से जोड़ने तथा उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उचित मूल्य दिलाने को कहा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने जशपुर जिला के कुनकुरी विकासखंड के बेहराखार ग्राम का दौरा कर विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके रहन-सहन, जीवनशैली को नजदीक से समझा और उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने बिरहोर समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों तक सभी शासकीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और वे मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बिरहोर समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर दिया।

राज्यपाल ने बिरहोर समुदाय के लोगों से संवाद करते हुए उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि बीमारी की स्थिति में अस्पताल या स्वास्थ्य शिविरों में जाकर समय पर उपचार कराना चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि बिरहोर समुदाय को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए संचालित पीएम जनमन योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे लोगों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य बताते हुए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को समय पर वैक्सीन लगवाने की अपील की।

राज्यपाल श्री डेका ने बिरहोर समुदाय के लोगों को अपने घरों में पढ़ाई के लिए एक अलग कोना बनाने की सलाह दी, जिससे बच्चों को अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके और वे अधिक प्रेरित हों। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि बिरहोर समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों का वैल्यू एडिशन किया जाए, ताकि उनके उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य मिल सके।

इस अवसर पर बिरहोर समुदाय के गुरुबारु ने राज्यपाल को जानकारी दी कि क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने पद्मश्री जागेश्वर यादव के सहयोग की सराहना भी की। कार्यक्रम के दौरान बिरहोर समुदाय के लोगों ने राज्यपाल का पारंपरिक रूप से स्वागत करते हुए उन्हें केंद फूल, लाटा तथा स्वयं निर्मित रस्सी भेंट की। राज्यपाल ने भी समुदाय के लोगों को साल भेंट कर सम्मानित किया तथा उपयोगी सामग्री के रूप में टॉर्च प्रदान की। साथ ही उन्होंने पद्मश्री जागेश्वर यादव को राजकीय गमछा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

पद्मश्री जागेश्वर यादव ने राज्यपाल रमेन डेका के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने उन्होंने बिरहोर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के अपने लंबे संघर्षों का उल्लेख भी किया। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 1980 से इस विशेष पिछड़ी जनजाति के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। उस समय बिरहोर समुदाय के लोग घने जंगलों में निवास करते थे, जंगलों से प्राप्त फलों पर निर्भर रहते थे और जमीन पर ही जीवन यापन करते थे। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को वतर्मान स्थिति तक लाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लगातार प्रयास, जागरूकता और शासन-प्रशासन के सहयोग से आज बिरहोर समुदाय के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है और वे धीरे-धीरे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

कलेक्टर रोहित व्यास ने राज्यपाल को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम बहेराखार में बिरहोर समुदाय के कुल 22 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 85 है। इनमें से 73 लोगों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। सभी परिवारों का सिकल सेल स्क्रीनिंग परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा सभी को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 19 परिवारों के जॉब कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। कुछ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्राप्त हो चुका है, जबकि शेष परिवारों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। महतारी वंदन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।

संपादकीय

बंगाल में अराजकता

संवैधानिक संस्थाओं की अग्निपरीक्षा

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है।

मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दर्शाने वाला है।

बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और समय रहते कारवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा जा सकता है।

जब राज्य में एसआईआर काम में लगे लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोगों में उपजे अविश्वास के मद्देनजर इस दिशा में सतर्क पहल जरूरी थी। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर विदेशियों की घुसपैठ की समस्या रही है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया द्वारा मतदाताओं की पड़ताल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते व जरूरी कागजों के उपलब्ध न होने से कुछ वैध मतदाताओं को अपनी वैधता की पुष्टि के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं को भी समझने की जरूरत है।

ऐसे मतदाताओं के अविश्वास को भी दूर करने की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर शुरू से ही नजर बनाये हुए है। चुनाव आयोग भी दावा कर रहा है कि किसी योग्य मतदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर निगरानी के मकसद से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की थी। लेकिन विडंबना है कि उन्हें ही आक्रोशित भीड़ ने बंधक बनाया। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तंत्र को लोगों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि राज्य के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के बजाय मतदाताओं को तकर्पूण ढंग से स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये प्रेरित करेंगे। राज्य में स्वतंत्र-निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनेताओं का संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरुरत थी?

अजीत द्विवेदी

विपक्षी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का उनका मकसद पूरा हो गया। वे देश को बताना चाहते थे कि स्पीकर ओम बिरला पक्षपात करते हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरे विपक्षी सांसदों को भी बोलने से रोका जाता है और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी बात है, जो विपक्ष के सांसद हमेशा नहीं कहते रहते हैं? जब भी सत्र चलता हा या नहीं भी चल रहा होता है तो जहां मौका मिलता है वहां ये बातें कही जाती हैं। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं था। एक औपचारिकता के तौर पर इसे पेश कर दिया गया।

ऐसा होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग नहीं कराई। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वह वोटिंग कराना चाहती थी लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह सही है कि इससे पहले जब भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वोटिंग नहीं हुई और प्रस्ताव ध्वनिमत से ही खारिज हुआ। लेकिन उस समय की स्थितियां अलग थीं। 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव आया था तब कांग्रेस के पास 415 सांसद थे। इसी तरह उससे पहले हुकुम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि 50 सांसद पूरे नहीं हुए। उससे पहले जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उस समय देश की पहली लोकसभा का मामला था, जिसमें कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था। लेकिन इस बार भाजपा को बहुमत नहीं है और एनडीए के पास भी 293 सांसद ही हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी को मिला कर विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। इतिहास में कभी भी विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहा है। विपक्ष को अपनी यह मजबूती संसद में दिखानी चाहिए थी, जो उसने नहीं दिखाई।

सवाल है कि क्या विपक्ष को अपने अंदर बिखराव की समस्या दिख रही थी? यह भी सवाल है कि अगर चर्चा के बाद वोटिंग नहीं करानी थी तो व्हिप जारी करने का क्या मतलब था? वास्तविकता सबको पता थी कि प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। फिर भी विपक्ष ने इसे पेश किया था तो चर्चा के बाद वोटिंग के लिए जोर देना चाहिए था। वोटिंग होती तो सरकार की ताकत का भी पता चलता। यह भी पता चलता है कि विपक्ष कितना एकजुट है। सरकार और विपक्ष दोनों से दूरी बना कर चलने वाले 17 सांसदों के रूझान का भी पता चलता। अगर विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाता तो शायद आगे उसकी बात ज्यादा सुनी जाती। लेकिन विपक्ष ने यह मौका गंवा दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया। उसका हस्र भी ऐसा ही होगा, जैसा स्पीकर के मामले का हुआ है और उस समय भी कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी, जो अभी नहीं कही जा रही है।

बहरहाल, वोटिंग के लिए दबाव नहीं डालने के अलावा कई और कारण हैं, जिनसे लग रहा है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं था। इसमें एक कारण तो यह है भी है कि जिस समय प्रस्ताव पेश किया गया उस समय विपक्ष में एकता नहीं दिखी। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी और दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर दस्तखत नहीं किए। तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इससे दूर रही। उसके सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत ही नहीं किए। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि उनके सांसद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस को तृणमूल और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों पर भरोसा नहीं रहा हो इसलिए वोटिंग के लिए दबाव नहीं डाला गया।

विपक्ष की अगंभीरता का पता इस बात से भी चलता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर किसी बड़े नेता ने बोलने की जरुरत नहीं समझी। कांग्रेस ने असम चुनाव का ध्यान रखते हुए गौरव गोगोई से भाषण की शुरुआत कराई। राहुल गांधी भी दूसरे दिन तब बोले, जब केसी वेणुगोपाल ने रविशंकर प्रसाद के भाषण के बाद प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और राहुल के जवाब देने के अधिकार की बात कही। इस पर आसन पर बैठे दिलीप पैकिया ने उनको बोलने का मौका दिया। विपक्ष की अगंभीरता सोमवार, नौ मार्च को दिखाई दी, जब सत्र शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने पश्चिम एशिया में चल रही जंग पर चर्चा कराने की मांग लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सोचें, यह पहले से तय था कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तो पहले दिन स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन पहले दिन विपक्ष पश्चिम एशिया में जंग पर चर्चा की मांग करने लगा। कोई चर्चा नहीं हुई फिर भी विपक्ष ने वह मांग छोड़ दी और 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो गया।

स्पीकर के खिलाफ चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया लेकिन पहले दिन सात घंटे में से सवा छह घंटे विपक्ष के हंगामे में खराब हो गए। सोचें, विपक्ष ने खुद ही प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव पर चर्चा में हंगामा ही होता रहा। पहले दिन सिर्फ 47 मिनट चर्चा हुई। अगले दिन जरूर छह घंटे की चर्चा चली। लेकिन उसके बाद ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। विपक्ष अगर वोटिंग कराता तो सत्तापक्ष की पार्टियों की एकजुटता का भी पता चलता। ध्यान रहे बिहार में जो कुछ हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह मौके का इस्तेमाल करते हैं उसे देखते हुए सरकार के संसदीय प्रबंधकों को ज्यादा मोलभाव करना पड़ सकता था। बहरहाल, कारण जो भी रहा हो वास्तविकता यह है कि बिना कोई प्रभाव छोड़े विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया।

ऊपर से ऐसा लगा, जैसे विपक्ष ने स्पीकर को जितना एक्सपोज करना चाहा उससे ज्यादा अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कर दिया। अमित शाह ने तथ्यों के साथ बताया कि राहुल गांधी 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य बन कर आए थे और 18वीं लोकसभा तक वे संसद की कार्यवाही में कितना शामिल हुए हैं। शाह ने बताया कि राहुल की उपस्थिति औसत से बेहतर नहीं है और उन्होंने ज्यादातर अहम मौकों पर संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और अहम विधायकों का मामला शामिल है। अमित शाह ने यह भी बताया कि पिछली लोकसभा में भाजपा के पास कांग्रेस से छह गुना ज्यादा सांसद थे फिर भी कांग्रेस को बोलने का ज्यादा समय दिया गया। तभी ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर लिया।

अनाज से ज्यादा अहम और क्या

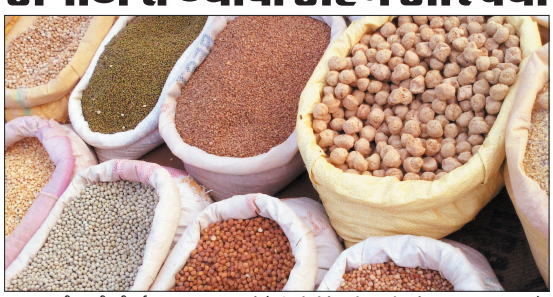

भारत अपनी 30 फीसदी उर्वरक जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है। मगर, कई उर्वरक जो देश में बनते हैं, उनकी इनपुट सामग्रियों पर ध्यान दें, ये तो निर्भरता 70 फीसदी तक बढ़ जाती है। क्या ये स्वस्थ स्थिति है?

अभी पिछले साल ही अमेरिका से व्यापार युद्ध के सिलसिले में जब चीन ने उर्वरकों का निर्यात रोका, तो उससे भारत भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। उसके पहले 2022 में रूस-यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तब भी भारत को उर्वरक आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ा था। अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उससे भी बड़ी समस्या खड़ी होती दिख रही है। युद्ध के लंबा खिंचने के साथ देश में उर्वरकों की उपलब्धता की चिंता हर दिन अधिक गहराती जा रही है। ध्यान देने की बात है कि उर्वरकों का संबंध देश की खाद्य सुरक्षा से है। किसी भी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता होनी चाहिए।

लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज खेती-बाड़ी से जुड़ी अनिवार्य चीजों के मामले में भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर बना हुआ है। मोटे आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी 30 फीसदी उर्वरक जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है। मगर, कई उर्वरक जो देश में बनते हैं, उनकी इनपुट सामग्रियों पर ध्यान दिया जाए, ये तो निर्भरता 70 फीसदी तक बढ़ जाती है। क्या ये स्वस्थ स्थिति है? पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक इस मामले में भारत सबसे ज्यादा निर्भर रूस (18.1 प्रतिशत), सऊदी अरब (15.7), चीन (15) और मोरक्को (14.8 प्रतिशत) पर था। जॉर्डन, ओमान, कतर, यूएई और मिस्र अन्य देश हैं, जिनसे भारत उर्वरक के इनपुट आयात करता है।

फिलहाल पश्चिम एशिया वाले तमाम देशों से आयात कठिन हो गया है। वहां जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन सामग्रियों की कीमत में भी भारी उछाल आया है। इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। पिछले साल केंद्र ने उर्वरक सब्सिडी के तौर पर 1.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस वर्ष इस मद में 1.71 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। जाहिर है, वास्तविक खर्च इससे काफी ज्यादा होगा। बहरहाल, मामला सिर्फ सब्सिडी बजट का नहीं है। मुद्दा है कि इस बारे में दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई जाती? क्यों नहीं इनपुट के स्रोतों का विस्तार कर उर्वरक उत्पादन का कार्य अपने देश में किया जाता? आखिर अनाज से ज्यादा अहम और क्या है?

श्रमिक हितों का ख्याल

इस दलील में दम है कि श्रम अधिकारों का मामला राजनीतिक दायरे में आता है, जिस बारे में निर्णय संसद या सरकार को ही लेना चाहिए। मगर जहां मुद्दा संवैधानिक अधिकारों से जुड़ता हो, वहां कोर्ट की भूमिका बन जाती है।

किन गतिविधियों को उद्योग माना जाए, यह तय करने की जिम्मेदारी फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ली है। मगर केंद्र ने उससे सहमत नहीं है। 1978 में उद्योग की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने तय की थी। अब उस पर पुनर्विचार करने के लिए कोर्ट ने नौ जजों की बेंच बनाई है। उसके सामने अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा कि कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र चाहता है कि सरकारी एवं समाज कल्याण से जुड़े कार्यों को औद्योगिक गतिविधि ना माना जाए। यह तर्क मंजूर होने का मतलब होगा कि इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मी श्रम कानूनों/ संहिताओं के तहत मिले अधिकार/ लाभ से वंचित हो जाएंगे।

जाहिर है, इस प्रकरण का संबंध श्रमिकों से भी है। इसलिए इस मामले में उनका पक्ष भी महत्त्वपूर्ण होगा। इस दलील में दम है कि श्रम अधिकारों से संबंधित पहलू राजनीतिक दायरे का हिस्सा हैं, जिनके बारे में निर्णय संसद या सरकार को ही लेना चाहिए। मगर जहां मुद्दा संवैधानिक अधिकारों से जुड़ता हो, वहां कोर्ट की भूमिका बन जाती है। इसीलिए 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति विभाग से जुड़े मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ का गठन करना पड़ा था। 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम जयवीर सिंह मामले में ये विवाद फिर उठा, जो अब तक लंबित है।

उसी सिलसिले में अब कोर्ट नौ जजों की बेंच बनाई गई है। 1978 में कोर्ट ने कहा था कि कोई संगठन उद्योग की श्रेणी में आता है या नहीं, यह तय करने की कसौटी यह नहीं हो सकती कि मुनाफा कमाना उसका मकसद है या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने तीन पैमाने तय किए: व्यवस्थित गतिविधि, प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच सहयोग, और वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण। इस तरह चैरिटी, सामाजिक कार्य एवं कल्याण कार्यों से जुड़े संगठन भी उद्योग के दायरे में आ गए। ये फैसला उस दौर में आया, जब वैचारिक दायरे में श्रमिकों के हित सवीपरि माने जाते थे। आज माहौल बदल चुका है। फिर भी श्रमिक हितों का ख्याल किया जाना चाहिए।

भारत में बच्चों की जिंदगियां बेतरतीब करते स्मार्टफोन

डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा

भारत में 50 प्रतिशत से अधिक किशोर रोज चार घंटे से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे पढ़ाई, खेल और परिवार से संवाद का समय कम हो जाता है। इससे मोटापा, आलस्य, थकान और कमजोर स्टैमिना की समस्याएं बढ़ रही हैं। 60 प्रतिशत बच्चों में नींद पूरी नहीं होने से उनमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा अपने भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता कमजोर होने लगती है। चार घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम वाले 25.9 प्रतिशत बच्चे अवसादग्रस्त पाए गए जबकि इससे कम स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में केवल 9.5 प्रतिशत ही अवसाद की समस्या पाई गई।

तकनीक ने मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेमिंग व ऐसे ही अन्य कई ऐप्स की लत से विश्व भर के बच्चों को एक खतरनाक और गंभीर स्थिति में ला दिया है। बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं, वे साइबर अपराधों के शिकार हो रहे हैं। मोबाइल के कारण बच्चे आत्महत्या कर लगे हैं। बच्चों के सामाजिक व शैक्षिक जीवन पर इसका बुरा असर हो रहा है।

140 करोड़ की जनसँख्या के इस देश में दिसंबर 2025 तक 124.42 करोड़ मोबाइल धारक और 1.02 करोड़ से अधिक इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हो गए हैं। हर माह प्रति व्यक्ति औसत डाटा की खपत 25 जीबी वाला हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा दूरसंचार बाजार है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन कक्षाए संचालित कर बच्चों की पढ़ाई करवाने के सरकारी फरमान के बाद स्कूली बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देना पालकों की विवशता हो गई। हालाकि केंद्र के सरकारी और ऊँची फीस वाले निजी स्कूलों में इन ऑनलाइन कक्षाओं का विधार्थियों ने भरपूर लाभ लिया और अपनी सीखना जारी रखा, लेकिन लाखों सरकारी व छोटे गैर-सरकारी स्कूलों में यह मात्र औपचारिकता ही रहा और विधार्थी सीखने में पिछड़ गए। इस समूची कवायद का हश्र यह हुआ कि आदिवासी व ग्रामीण बसाहटों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के अधिकतर बच्चों को छोड़ कर देश भर के करोड़ो बच्चों के हाथों में यह उपकरण आ गया। सूचना, ज्ञान, संचार, वित्तीय लेनदेन और नियंत्रित मनोरंजन जैसी मूल आवश्यकताओं पीछे छोड़ ज्यादातर बच्चे इस उपकरण का व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, यू-ट्यूब व गेमिंग के एप्स, सेल्फी, विडियो व रील बनाने आदि में जरुरत से बेहिसाब ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। घंटों स्क्रीन पर अपनी आँखें और ध्यान गड़ाए रख आभासी दुनिया में विचरण करने लगते हैं। यह स्थिति कई चिंताए पैदा करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन जैसी मानक संस्थाओं के अध्ययनों के अनुसार भारत में 2 साल से कम उम्र के 61 प्रतिशत बच्चे स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 2 साल तक के बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं दिखानी चाहिए। भारत में 50 प्रतिशत से अधिक किशोर रोज चार घंटे से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे पढ़ाई, खेल और परिवार से संवाद का समय कम हो जाता है। इससे मोटापा, आलस्य, थकान और कमजोर स्टैमिना की समस्याएं बढ़ रही हैं। 60 प्रतिशत बच्चों में नींद पूरी नहीं होने से उनमे चिड़चिड़ापन और गुस्सा की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा उनमें भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता कमजोर होने लगी है। चार घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम वाले 25.9 प्रतिशत बच्चे अवसादग्रस्त पाए गए जबकि इससे कम स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में केवल 9.5 प्रतिशत ही अवसाद की समस्या पाई गई।

बाजार की जरूरतों के मद्देनज?, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेमिंग सहित कई लुभावनी एप्स को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह बच्चे लंबे समय तक मोबाइल से बंधे रहें और इसके इस्तेमाल की लत के शिकार हो जावें। लत में पड़ कर वे देर रात तक जाग रहे हैं, नींद पूरी न होने से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, आत्म विश्वास कम हो रहा है। दूर तक देखने की क्षमता कम होने सहित नेत्र दोषों के शिकार हो रहे बच्चे। स्थिति यह हो जाती है कि वे मोबाइल के उपयोग से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। बार-बार व्हाट्सअप, फेसबुक या इंट्राग्राम पर पोस्ट चेक करते हैं। यहाँ तक बाथरूम में भी मोबाइल साथ रहता है। मोबाइल के बिना रहने, नेटवर्क न मिलने या फोन खो जाने का तकर्हीन डर उनमे बना रहता है। पोस्ट पर आने वाली लाइक्स और कमेंट्स उनके इए व्यक्तित्व की स्वीकृति का आधार बन उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती हैं। यह स्थिति नोमोफोबिया नामक एक आधुनिक मानसिक विकार है, जो 12 से 23 वर्ष के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, चिंता, घबराहट, कांपना, पसीना आना, अकेलापन, और अवसाद इसके लक्षण हैं। कुछ बच्चों पर मोबाइल इस कदर हावी होता जा रहा है कि वे वर्चुअल दुनिया में खोये से रहते हैं। रोकने-टोकने पर तनावग्रस्त होकर क्रोध में आ जाते हैं, आपा खोकर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। मोबाइल के उपयोग पर सक्ती से मनाही करने या मोबाइल छुड़ा लेने की स्थिति में कई बार बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। मोबाइल के कारण बच्चों द्वारा आत्महत्या किए जाने के खबरें कहीं न कहीं से रोज सुनने को मिलती हैं।

फेसबुक व इंस्ट्राग्राम पर अनियंत्रित आपत्तिजनक, अश्लील, उत्तेजक व बहलाने-फुसलाने वाले कंटेंट, बच्चों को गलत कामों, अपराधों, यौन उत्पीडन, ब्लेकमेलिंग और मानव तस्करी जैसे खतरों में धकेल रहे हैं। संसद में सरकार ने बताया है कि 2001 से 2023 तक दो वर्षों में बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध 38 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि कुछ राज्यों जैसे केरल में 172 प्रतिशत, उत्तराखंड में 178 प्रतिशत, कर्नाटक में 121 प्रतिशत व छत्तीसगढ़ में 119 प्रतिशत की चिंताजनक बढ़ौतरी दर्ज की गई है। भारत सरकार ने इस साल के इकोनामिक सर्वे में 'डिजिटल एडिक्शन' को बड़ा स्वास्थ्य के देखभाल का मुद्दा माना है।

हमारे देश में लचर साइबर कानूनों व अप्रभावी नियंत्रण नीतियों के कारण भारत में बच्चे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टारगेट पर हैं। पालक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाए और नागरिक संगठन बच्चों से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर मुखर नहीं हैं। अमेरिका की न्यू मैक्सिको में एक कोर्ट ने एक स्कूल द्वारा दायर वाद पर अभी ही दिए एक फैसले में मेटा को बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में नाकाम रहने का दोषी मान कर मेटा पर 3141 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है। हालाकि, मेटा ने अपनी पिछली तिमाही में इससे 160 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाया था। भारत में कड़े कानूनों और ऐसी जागरूकता की जरूरत है ताकि इन मुनाफाखोर कंपनियों पर नकेल कसी जा सके।

वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर लघु धान्य रागी से समृद्धि की ओर बढ़ती शकुन कुजांम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य और केन्द्र सरकार लघु धान्य जैसे रागी, कोदो, कुटकी जैसे फसलों को बढ़ावा देने किसानों विशेष अभियान चलाकर जागरूक कर रही है, इसी कड़ी में धमतरी विकासखंड के ग्राम उरपुटी की महिला कृषक श्रीमती शकुन बाई कुजांम लघु धान्य फसल रागी का उत्पादन कर प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में शामिल हो गई है।

गौरतलब है कि श्रीमती कुंजाम ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत, लगन और कृषि विभाग के

मार्गदर्शन से सफलता की एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। शकुन बाई के पास कुल 7 एकड़ कृषि भूमि है, जो ट्यूबवेल से सिंचित है। उनके पास ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप थ्रेसर एवं रीपर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हैं।

उनके परिवार के 5 सदस्य खेती में सक्रिय सहयोग करते हैं, जिससे कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाता है।

श्रीमती शकुन बाई ने बताया कि रबी सीजन में 3 एकड़ क्षेत्र में लघु धान्य फसल रागी (छत्तीसगढ़ रागी-2) की खेती की। उन्होंने बीजोपचार के लिए बीजामृत, तथा खाद के रूप में वर्मी कम्पोस्ट, डीएपी, पीएसबी एवं केएसबी का उपयोग किया। वैज्ञानिक विधियों से की गई खेती के परिणामस्वरूप उन्हें 28.50 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। कुछ वर्ष पहले बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत रागी की खेती से उन्हें 5200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 1,48,200 रुपये की आय हुई। इस उत्पादन में कुल लागत 27,000 रुपये रही, जिससे उन्हें 1,21,200 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित आत्मा कार्यक्रम के तहत उन्हें निरंतर मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने फसल चक्र परिवर्तन और लघु धान्य फसलों की खेती को सफलतापूर्वक अपनाया। फसल कटाई के बाद वे ग्रीष्मकालीन जुताई भी करती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इस प्रेरक सफलता की जानकारी मिलने पर जिले के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा स्वयं शकुन बाई के घर पहुंचे और उनकी खेती-किसानी के संबंध में बातचीत की। उन्होंने शकुन बाई की सराहना करते हुए इसे जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर शकुन बाई ने अपनी बाड़ी में उगाए गए मुनगा (सहजन) को भेंट स्वरूप प्रदान किया तथा पारंपरिक पत्तल-दोना में माड़िया पेय से स्वागत किया। यह ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भरता का सुंदर उदाहरण रहा।

शकुन बाई की यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान का समन्वय करें, तो कम लागत में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। उनकी सफलता न केवल उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का आधार बनी है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बनी है।

खास खबर

क्षत्रिय वीरांगना महासभा की बैठक समाज सशक्तिकरण को लेकर तय हुई रणनीति

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

अखिल भारतीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा की बैठक खैरागढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रदेश अध्यक्ष सुषमा सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह गहरवार, अध्यक्ष राजकुमारी शताक्षी देवव्रत सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय वीरांगना महिलाएं उपस्थित रहीं।

बैठक का मुख्य फोकस समाज के मूल उद्देश्यों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने पर रहा। इस दौरान संगठन की महिलाओं ने एकमत होकर समाज में शिक्षा का प्रसार महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा क्षत्रिय संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी महाराणा प्रताप जयंती को भव्य एवं प्रेरणादायक रूप में मनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई।

वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और नई पीढ़ी में प्रेरणा जगाने का माध्यम बनेगा। बैठक में महिलाओं से संगठन से अधिकाधिक जुड़कर समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठ परिवारजनों का सहयोग भी आत्मीय रूप से मिला। अध्यक्ष राजकुमारी शताक्षी देवव्रत सिंह सहित समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी की उपस्थिति में यह बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

धर्म की आजादी पर हमला बर्दाश्त नहीं- "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026" के खिलाफ मूल निवासी संघ का बड़ा ऐलान

भिलाई। मूल निवासी संघ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026" के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। संघ ने इस विधेयक को सीधे सीधे संविधान और मौलिक अधिकारों पर हमला बताते हुए राज्यपाल से इसे तत्काल खारिज करने की मांग की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 को कमजोर करने की साजिश है। धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने के अधिकार को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। संविधान की आत्मा के खिलाफ कानून संविधान की उद्देशिका में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता को यह विधेयक कुचलने का प्रयास करता है। "प्रलोभन" की आड़ में समाज सेवा पर वार दान, शिक्षा, इलाज, मदद सबको "प्रलोभन" बताकर अपराध बनाने की तैयारी। अनाथालय, स्कूल, अस्पताल भी शक के घेरे में आ जाएंगे।

अस्पष्ट कानून - मनमानी कार्रवाई "बल", "कपट", "असम्यक प्रभाव" जैसे शब्द इतने अस्पष्ट हैं कि कोई भी फंस सकता है। झूठे केस, उत्पीड़न और डर का माहौल बनेगा। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप संघ ने कहा- यह कानून खास समुदायों को टारगेट करने का हथियार बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन वऊलफ और कउउढफजैसे वैश्विक मानवाधिकार मानकों की खुलेआम अनदेखी।

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित जब पूरा मामला पहले से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो नया कानून लाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। 2006 का उदाहरण सरकार भूली पहले भी ऐसा संशोधन विधेयक रोका जा चुका है। फिर वही गलती दोहराई जा रही है। मूल निवासी संघ ने कहा - अगर इस विधेयक को अनुमति दी गई तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन होगा। सड़कों से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। "धर्म की आजादी कोई सौदेबाजी नहीं है इसे छीनने की कोशिश हुई तो जवाब भी उतना ही कड़ा होगा।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल से शीतल टंडन की शिक्षा को मिला संबल

11वीं में 90 प्रतिशत अंक के साथ किया टॉप

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

केबिनेट मंत्री एवं तत्कालीन दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की संवेदनशील पहल से वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती निवासी धर्मेंद्र टंडन की सुपुत्री शीतल टंडन की शिक्षा को नया संबल मिला। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छूटने की स्थिति में पहुंच चुकी शीतल को मंत्री गजेन्द्र यादव ने तत्काल सहयोग प्रदान करते हुए खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाया। उनकी इस मानवीय पहल का परिणाम है कि शीतल ने कक्षा 11वीं (आर्ट्स संकाय) में 90 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है।

शीतल के पिता धर्मेंद्र टंडन एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता प्रीति टंडन गृहणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 10वीं के बाद शीतल की आगे की पढ़ाई संकट में पड़ गई थी। ऐसे कठिन समय में

परिजनों ने मंत्री गजेन्द्र यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर बेटी की शिक्षा जारी रखने में सहयोग की अपील की थी।

मंत्री श्री यादव ने तत्परता दिखाते हुए शीतल का खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश कराया, जिससे उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। शीतल ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए पूरी लगन और मेहनत से अध्ययन किया और कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

आज गंजपारा स्थित कार्यालय में मंत्री गजेन्द्र यादव ने शीतल टंडन को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि "प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन और अवसर की।" उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

भवन निर्माण के लिए 121.16 लाख रुपए प्रशासकीय राशि की मिली स्वीकृति

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक आदर्श कन्या शाला के भवन निर्माण हेतु 121.16 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह विद्यालय बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने हेतु जिले का एक पुराना एवं महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है।

नवीन भवन निर्माण से छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग संभाग राजनांदगांव द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। निर्माण स्थल पर स्थित अत्यंत पुराने एवं जर्जर आवासीय भवन, जो कमर्चारियों के निवास के लिए अनुपयुक्त हो चुके थे, को वर्तमान में डिस्मेंटल किया जा रहा है। जर्जर भवनों के हटने के पश्चात शीघ्र ही नवीन स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

शिविरों और घर-घर संपर्क से उपभोक्ताओं को मिल रहा समाधान योजना का लाभ

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दुर्ग नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले दुर्ग शहर संभाग, भिलाई (पूर्व)शहर संभाग और भिलाई (पश्चिम) शहर संभाग में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

अधीक्षण अभियंता जे. जगन्नाथ प्रसाद ने बताया कि 1 अप्रैल तक दुर्ग नगर वृत्त में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पंजीयन करा लिया है। अब तक 184 पात्र बीपीएल उपभोक्ताओं में से 173 ने पंजीयन कराया है, जिन्हें ?3,20,609 की छूट दी जाएगी। इसी तरह, 1688 पात्र एपीएल उपभोक्ताओं में से 1109 ने पंजीयन कराया है, जिन्हें ?13,49,674 की राहत मिलेगी। कृषि श्रेणी में भी 46 में से 40 पात्र उपभोक्ताओं ने पंजीयन पूर्ण कर लिया है, जिन्हें ?32,365 की छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 13 मार्च 2026 से सभी 12 जोनों के विभिन्न वार्डों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए माइक युक्त गाड़ियों का उपयोग कर पात्र उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसका क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए विभाग के कमर्चारी और मीटर रीडर घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। मीटर रीडरों को इस कार्य के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकें। 10 अप्रैल 2026 तक दुर्ग नगर वृत्त के सभी पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें शासन द्वारा दी जा रही इस सुविधा का पूर्ण लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

राशनकार्ड ई-केवाईसी के लिए विशेष शिविर, छूटे सदस्यों का होगा सत्यापन

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार जिले में राशनकाडर्धारियों के ई-केवाईसी से वंचित सदस्यों का डाटा संकलन सुनिश्चित करने हेतु खाद्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।

इसी क्रम में रविवार, 5 अप्रैल को पिपरिया नगर पंचायत क्षेत्र में चार अलग-अलग स्थानों पर विशेष ई-केवाईसी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में राशनकार्ड से जुड़े ऐसे सदस्यों का सत्यापन किया जाएगा, जिनका अब तक ई-केवाईसी नहीं हो सका है। विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर

प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

वहीं बोड़ला, पण्डरिया, पांडातराई और सहसपुर लोहारा क्षेत्रों में यह विशेष शिविर सोमवार, 6 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए समय पर ई-केवाईसी पूर्ण कराने का आग्रह किया है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से लिया जा सके।

क्रीड़ा भारती की प्रांत बैठक में संगठन विस्तार पर दिया जोर

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

क्रीड़ा भारती छत्तीसगढ़ प्रांत की योजना बैठक रायपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी प्रांत सम्मेलन को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई।

बैठक में जून माह में बिलासपुर में प्रस्तावित प्रांत सम्मेलन, कबड्डी प्रतियोगिताओं के आयोजन और सालभर चलने वाले पंचसूत्रीय कार्यक्रमों को भव्य रूप देने पर चर्चा की गई। साथ ही खंड स्तर तक गतिविधियों के विस्तार और ह्लपंच परिवर्तनह्व विषय पर भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई।

बैठक में कवर्धा जिले से प्रांत टोली सदस्य जसविंदर बग्गा और जिला मंत्री गिरीश चंद्रवंशी शामिल हुए। इस दौरान जसविंदर बग्गा ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित प्रांत सम्मेलन दो दिवसीय होना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं को आपसी संवाद और विचार-विमर्श का अधिक अवसर मिल सके। उनके इस सुझाव को सभी पदाधिकारियों ने सहमति दी।

बैठक के समापन सत्र में मध्य क्षेत्र संयोजक अनंत डी के जी ने समाज के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और संगठन को हर जिले तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। प्रांत मंत्री सुमित उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावों और वर्षभर आयोजित होने वाले कबड्डी मैचों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने क्रीड़ा केंद्रों के महत्व पर जोर देते हुए हर जिले में कम से कम 10 क्रीड़ा केंद्र शुरू करने का लक्ष्य रखा।

कल जिलेभर में मनाया जाएगा 'चावल उत्सव'

कवर्धा। खाद्य विभाग द्वारा जिले में आगामी 7 अप्रैल को चावल उत्सव के आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सभी 516 उचित मूल्य की राशन दुकानों में इस दिन एक साथ खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने इसके लिए खाद्यान्न के समयबद्ध भंडारण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। परिवहनकर्ताओं एवं संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी राशन दुकानों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। चावल उत्सव के दौरान सतकर्ता समिति के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति मे खाद्यान्न वितरण का कार्य संपन्न किया जावेगा। साथ ही आम हितग्राहियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। खाद्य विभाग ने बताया कि इस विशेष आयोजन का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना और हितग्राहियों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने नजदीकी राशन दुकानों में पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त करें और इस उत्सव का हिस्सा बनें।

स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार, मिलीं 6 संजीवनी 108 एम्बुलेंस

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग, जिला बेमेतरा को 6 नई संजीवनी 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और अधिक प्रभावी एवं सुलभ हो सकेंगी। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 31 मार्च को 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट संजीवनी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसी क्रम में बेमेतरा जिले को 6 एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिनमें 2 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (अछर) एवं 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट (इछर)

एम्बुलेंस शामिल हैं।

जिला चिकित्सालय बेमेतरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू एवं साजा विधायक ईश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंसों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, पार्षद नीतू कोठारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन एम्बुलेंसों के माध्यम से गंभीर एवं आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही मरीजों को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त बनेंगी।

इन एम्बुलेंसों की सुव्यवस्थित तैनाती की गई है, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय बेमेतरा में उपलब्ध रहेंगी, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सीएचसी साजा, बेरला, नवागढ़ एवं नांदघाट में तैनात रहेंगी, इससे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। नई एम्बुलेंसों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें शामिल हैं, बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सपोर्ट एवं नेबुलाइजेशन सुविधा, पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, लैरिंजोस्कोप इन सुविधाओं के माध्यम से मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक एवं उन्नत उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पहल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।

हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति की साप्ताहिक बैठक सेक्टर -2 शक्ति सदन में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रबंधन के सूचना के माध्यम से विभिन्न शर्तों के साथ पुनः रुआबंधा सेक्टर स्थित व उ-3 टाइप के अत्यंत जर्जर आवासों के लिए एक वर्ष पूर्व जारी लाइसेंस योजना को विभिन्न शर्तों के साथ पुनः जारी करने को उपस्थित सदस्यों ने तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि 2001-2003 के मध्य लीज योजना जो 30-30-30 अर्थात 90 वर्ष के लिए पट्टे में आवंटन हेतु प्रबंधन ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखा था बल्कि लिखित तौर पर आलू के भाव में जमीनों को पट्टे पर दिया गया था ।

लाइसेंस योजना भी प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर समस्त वैध-अवैध कब्जाधारियों को मात्र दस हजार में भी दिया गया था। जब

नए कार्मिकों की भर्ती संयंत्र में सुनियोजित तरीके से बंद कर दी गई है तब प्रबंधन की है हठ-धर्मिता मात्र तुगलक शाही ही है । प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है अतः वह भिलाई की जनभावना को नकार रहे हैं। यह तथ्य भी छुपा नहीं है कि किसानों से ली गई जमीन को आज मनमानी तरीके से मनचाहा आवंटन आज भी किया जाता है।

अंततः उपस्थित सदस्यों ने इस नारे के साथ कि हम मुक्तिधाम जाएंगे अपने वतर्मान आवास से ही के साथ इसे ही अपना निर्णय बताया। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया तथा लोकतांत्रिक आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। आज की बैठक में पी.आर.वर्मा, रमेश पाल, राजेंद्र शर्मा, धोडिया जी, के. साहू, नंदकुमार वर्मा, गौर जी, एस.के. भरने, तुलसी साहू सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

बचने के उपाय

यह परामर्श उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो थायराइड की दवाओं के बावजूद सुधार महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने आहार में इन पांच चीजों को संतुलित करें और कच्ची सब्जियों के बजाय पका हुआ भोजन अपनाएं। नियमित व्यायाम और सही खान-पान ही थायराइड को नियंत्रित करने की असली कुंजी है। ध्यान रखें छोटी-छोटी सावधानियां आपको जीवनभर दवाओं के बोझ से बचा सकती हैं।

आयोडीन और चीनी

आयोडीन थायराइड के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी अति नुकसानदेह है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन या आयोडाइड साल्ट का सेवन थायराइड फंक्शन को ब्लॉक कर सकता है। इसी तरह अत्यधिक चीनी, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, जो सीधे थायराइड हार्मोन के मार्ग को बाधित करता है। चीनी का सेवन कम करके आप अपने थायराइड को फिर से सक्रिय बना सकते हैं।

कच्ची क्रूसिफेरस सब्जियां

अक्सर लोग वजन घटाने के लिए पत्ता गोभी, फूलगोभी और ब्रोकली जैसी क्रूसिफेरस सब्जियों का सलाद खाते हैं। डॉक्टर शालिनी के अनुसार इन सब्जियों को कच्चा खाना थायराइड के लिए खतरनाक हो सकता है। इनमें ग्वाइट्रोजेन्स होते हैं जो आयोडीन के अवशोषण को रोकते हैं। इन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाकर या उबालकर ही खाएं, जिससे इनके हानिकारक तत्व निष्क्रिय हो जाएं और थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर न पड़े।

इन चीजों के सेवन से बढ़ जाता है थायराइड

आजकल की भागदौड़ भरी जीवनशैली में थायराइड की समस्या एक आम बीमारी बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ हेल्दी दिखने वाली चीजें ही आपके थायराइड हार्मोन के काम में बाधा डाल सकती हैं? विशेषज्ञों के अनुसार ये खाने-पीने की पांच बड़ी गलतियां आपको हाइपोथायरायडिज्म का शिकार बना सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जब हम कुछ खास खाद्य पदार्थों का गलत तरीके से या कच्चा सेवन करते हैं, तो वे शरीर में थायराइड हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक करने लगते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने, थकान और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, लेकिन गलत आहार इसे सक्रिय होने से रोकता है। इसलिए आहार में बदलाव करके इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है।

सोया उत्पाद

सोया चंक्स, टोफू और अन्य सोया उत्पादों को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों के लिए यह हानिकारक हो सकते हैं। सोया में मौजूद आइसोफ्लेवोन्स थायराइड हार्मोन के उत्पादन में हस्तक्षेप करते हैं। खासकर कच्चा सोया या इसका अत्यधिक सेवन हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो सोया उत्पादों के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

जंक और प्रोसेस्ड फूड

बेकरी आइटम्स, पैकेट स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड थायराइड के बड़े दुश्मन हैं। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि इनमें मौजूद ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव्स शरीर में इंफ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाते हैं। यह सूजन इम्यूनिटी पर बुरा असर डालती है, जिससे थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। स्वस्थ थायराइड के लिए पैकेट बंद फूड्स को अपनी डाइट से पूरी तरह बाहर करना ही बेहतर है।

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' का टीजर हुआ रिलीज

एक ओर जहां रणबीर कपूर की 'रामायण' के टीजर की धूम देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त की आगामी फिल्म 'आखिरी सवाल' का भी टीजर कल रिलीज हो गया है। ये टीजर देश के इतिहास में घटी कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कई सवाल उठाता है। इसके साथ ही फिल्म की कहानी के बारे में भी हिंट मिलती है।

1 मिनट 52 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत संजय दत्त के वॉइस ओवर से होती है। इसमें वो द्रौपदी के पिता द्रुपद के बारे में बताते हैं। कैसे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए भेजा। इस कहानी के बाद टीजर में एंट्री होती है संजय दत्त

की जो प्रोफेसर बने हैं और नमाशी चक्रवर्ती की, जिन्होंने विकी हेगड़े की भूमिका निभाई है।

आखिरी सवाल विक्की (नमाशी चक्रवर्ती) की कहानी है, जो एक युवा विद्वान है और अपने गुरु प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) के साथ उसका अकादमिक विवाद टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले एक टकराव में बदल जाता है। यह कहानी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए पीढ़ीगत मतभेद और सच की खोज जैसे मुद्दों पर बात करती है। कहानी के केंद्र में गुरु-शिष्य का संघर्ष है, जो एक बड़ी बहस में बदल जाता है। टीजर में महात्मा गांधी की हत्या, आरएसएस पर बैन, बाबरी विध्वंस जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र देखने को मिलता है।

8 मई को रिलीज होगी फिल्म

टीजर में संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती के अलावा फिल्म की बाकी कास्ट भी नजर आती। इसमें अमित साध, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकारों की झलक दिखती है। अभिजीत मोहन वारंग द्वारा निर्देशित आखिरी सवाल 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण निखिल नंदा और संजय दत्त ने किया है, जबकि पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्ज्वल आनंद फिल्म के सह-निर्माता हैं।

बॉलीवुड | मन की बात

मैं और ऐश्वर्या दोनों मिलकर बेटी की परवरिश करते हैं : अभिषेक

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के उन कपल्स में गिने जाते हैं, जिनके रिश्ते को लेकर सालों से तरह-तरह की बातें होती रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग होने और तलाक की खबरें भी उड़ती रहीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अक्सर साथ नजर आए। हाल ही में अभिषेक ने एक इंटरव्यू में इन सब बातों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने रिश्ते, परिवार और बेटी की परवरिश को लेकर अपनी सोच शेयर की। उनकी बातें सुनकर साफ समझ आता है कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि समझ और भरोसे पर टिका है। हाल ही में लिली सिंह को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वे और ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या की परवरिश मिलकर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में कोई एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है। दोनों अपने-अपने तरीके से जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनकी ये बात फैंस को खूब पसंद आई। अभिषेक की बातों से ये भी साफ हुआ कि उनके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बराबरी की साझेदारी है, जहां दोनों की सोच और मेहनत को बराबर अहमियत दी जाती है। अभिषेक ने अपने रिश्ते को लेकर कहा, 'मेरे माता-पिता की शादी के समय मेरी मां मेरे पिता से बड़ी स्टार थीं। इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी'। उन्होंने बताया कि वे ऐश्वर्या को अपने करियर की शुरुआत से जानते हैं। उनकी दूसरी फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' में दोनों साथ काम कर चुके थे। उस समय दोनों सिर्फ दोस्त थे। धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर रिश्ता आगे बढ़ा। अभिषेक ने कहा कि उनके बीच कभी ये बात नहीं हुई कि कौन क्या करेगा या किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? सब कुछ अपने आप चलता गया। उन्होंने आगे कहा, 'हमारे रिश्ते में हमेशा साझेदारी रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कमाऊं और वो घर संभालें या ऐसा कोई बंटवारा हो'।

सैयारा के बाद एक्शन-रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहे हैं अहान पांडे

सैयारा फेम एक्टर अहान पांडे एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे। शुक्रवार को अली अब्बास जफर ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए फिल्म से अहान पांडे का पहला लुक शेयर किया है, जिस पर फैंस दिल हार बैठे हैं।

अहान पांडे की इस फिल्म की शूटिंग शुक्रवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। जल्द ही मुख्य अभिनेत्री और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की जाएगी। फिल्म का निर्माण वाईआरएफ कर रहा है। इसकी शूटिंग मुंबई और विदेशों में होगी। इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर अहान की एक खास तस्वीर शेयर की और लिखा, और शुरू हो गई...

अहान पांडे की इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर अहान पांडे की है। इस तस्वीर में अहान के चेहरे का कुछ हिस्सा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी की तस्वीर धुंधली है। छोटे बाल में अहान का यह लुक कमाल का लग रहा है। इस तस्वीर

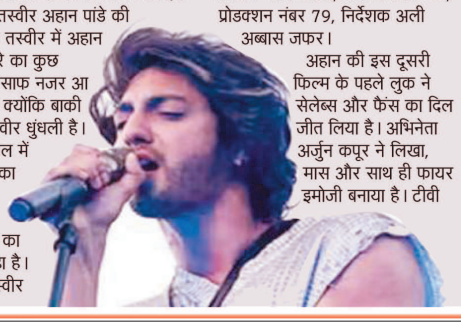

को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह किसी को देखते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर एक क्लैप बोर्ड की है। जिसके साथ लिखा, यश राज फिल्म्स, प्रोडक्शन नंबर 79, निर्देशक अली अब्बास जफर।

अहान की इस दूसरी फिल्म के पहले लुक ने सेलेब्स और फैंस का दिल जीत लिया है। अभिनेता अर्जुन कपूर ने लिखा, मास और साथ ही फायर इमोजी बनाया है। टीवी अभिनेता हितेन तेजवानी ने लिखा, बधाई हो अली सर, अहान की मां डीन ने लिखा, पूरी टीम को शुभकामनाएं, रजत बेदी ने लिखा, बधाई हो अली भाई, एक फैन ने लिखा, बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, दूसरे फैन ने लिखा, अहान तुम कमाल कर दोगे, वहीं कई फैंस अहान के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

सैयारा जैसी लव स्टोरी करने के बाद अब एक्शन-रोमांस फिल्म में आहान को एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की पांचवीं फिल्म है, जिनकी जोड़ी ने मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी हिट फिल्में दी हैं।

आईपीएस अधिकारी का फिल्म खौफ-द डिजिटल वॉर रिलीज, डीजीपी गौतम ने दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

जशपुर के विशिष्ट कम्युनिटी हॉल सभागार में साइबर फ्रॉड पर आधारित शॉर्ट फिल्म "खौफ - द डिजिटल वॉर" का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय एवं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जशपुर के विशिष्ट प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, गणमान्य नागरिकों, फिल्म खौफ की टीम उपस्थित रही। विदित हो कि एसएसपी शशि मोहन सिंह समाज के ज्वलंत मुद्दों पर लगातार शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने जशपुर में रहते हुए "कजरी" फिल्म का निर्माण किया था। राष्ट्रीय

नाट्य मंचन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से "खौफ - द डिजिटल वॉर" का निर्माण किया।

इस फिल्म की कहानी स्वयं एसएसपी शशि मोहन सिंह ने लिखी है। उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है तथा फिल्म में एक पीड़ित शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके सुपुत्र "ऋषु समर्थ सिंह" भी फिल्म में प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए-नए तरीकों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित फिल्म खौफ की टीम के प्रवीण अग्रवाल, कुंदन सिंह, ऋषु समर्थ सिंह, वंशिका गुप्ता, लायरा जैन, राम प्रकाश पाण्डेय ने मंच से फिल्म निर्माण को लेकर अपने अनुभव साझा किया। सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने फिल्म की सराहना की और इसे समाज के लिए एक उपयोगी एवं प्रेरणादायक पहल बताया।

फिल्म विमोचन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या देवी साय जी ने कहा कि एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह फिल्मों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड पर आधारित यह फिल्म लोगों को जागरूक करने में प्रभावी साबित होगी। उन्होंने पूरी पुलिस टीम एवं फिल्म से जुड़े कलाकारों को शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने भी एसएसपी शशि मोहन सिंह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जशपुर में हो रहे नाट्य मंचन की प्रशंसा करते हुए स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म के जागरूकता संदेशों का सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर अपराधों के प्रति जागरूक हो सकें। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के प्रमुख डॉ. आनंद पाण्डेय जी ने कहा कि - "एसएसपी शशि मोहन सिंह और मेरे द्वारा इस नाटक के महोत्सव की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय कलाकारों को एक मंच के साथ लघु फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिल रहा है। "जशरंग महोत्सव" का कारवां आगे भी जारी रहेगा। एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश "फिल्म को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म का उद्देश्य साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना है। लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसका प्रचार-प्रसार करें, ताकि फिल्म का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके।

खास खबर

स्वास्थ्य क्रांति, 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' से सुदूर वनांचल के ग्रामीणों को मिल रही नई सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए संचालित 'नियद नेल्लानार' (आपका अच्छा गाँव) योजना अब धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही है। जिला बीजापुर के दुर्गम क्षेत्र ग्राम पालनार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के खुलने से 28 जनवरी 2026 से अब तक सैकड़ों ग्रामीणों को उनके घर के समीप ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रिकॉर्ड ओपीडी और इनडोर सुविधाएं

पालनार और आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य के प्रति आई इस जागरूकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अल्प अवधि में ही कुल 747 मरीजों ने ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार 16 मरीजों को भर्ती कर उनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया। पहले जिन ग्रामीणों को छोटी बीमारियों के लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता था, उन्हें अब विशेषज्ञ परामर्श और निःशुल्क दवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल रही हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस केंद्र में अब तक 5 सुरक्षित प्रसव कराए गए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप, नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। साथ ही, क्षेत्र की 15 गर्भवती महिलाओं और 18 धात्री माताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है।

योजना के तहत गैर-संचारी रोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पालनार केंद्र में अब तक 250 ग्रामीणों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 25 मरीज उच्च रक्तचाप से ग्रसित पाए गए। बारह मरीज मधुमेह से पीड़ित मिले। एक ग्रामीण में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण मिलने पर तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र हेतु रेफर किया गया। पालनार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सफलता यह दर्शाती है कि शासन की योजनाएं अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, बल्कि ग्रामीणों का प्रशासन के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।

आत्मसमर्पण से आत्मनिर्भरता : सुकमा में युवाओं को मिली नए जीवन की मजबूत नींव

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मानवीय, संवेदनशील एवं दूरदर्शी पुनर्वास नीति अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिला प्रशासन लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है, जिससे आत्मसमर्पित माओवादी युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी क्रम में जिला मुख्यालय सुकमा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में 32 आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगारोन्मुख मेसन (राजमिस्त्री) किट प्रदान की गई। कार्यक्रम कलेक्टर अमित कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने युवाओं से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि पुनर्वास केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है।

हमारा लक्ष्य है कि आप सभी को स्थायी आजीविका, आत्मनिर्भरता और समाज में सम्मान मिले। आज दी जा रही मेसन किट केवल औजार नहीं, बल्कि आपके नए जीवन की मजबूत नींव है। निर्माण कार्यों में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजमिस्त्री का कार्य ऐसा कौशल है जिससे आप मेहनत और ईमानदारी के बल पर कुशल कारीगर बनकर आगे चलकर स्वरोजगार, ठेकेदारी और उद्यमिता की ओर भी बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और प्रशिक्षण व अनुशासन के साथ अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। इस पहल के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पुनर्वास का अर्थ केवल मुख्यधारा में लौटना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीवन को नई दिशा देना है। मेसन किट मिलने से युवाओं को निर्माण कार्यों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे।

कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं : विधायक मिश्रा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का भव्य शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जवाहर नगर मंडल (जिला रायपुर) द्वारा आयोजित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान - 2026' का शनिवार को समता कॉलोनी स्थित रामनाथ भीमसेन भवन में शुभारंभ हुआ। विधायक पुरंदर मिश्रा एवं प्रदेश व जिला मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर शिविर की शुरुआत की।

मंडल के अध्यक्ष संदीप जंगल एवं मीडिया प्रभारी प्रणीत जैन ने बताया कि दो दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को वैचारिक और सांगठनिक रूप से सुदृढ़ करने की मुहिम शुरू की गई है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने सर्वप्रथम प्रशिक्षण स्थल पर लगी विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों, जवाहर नगर मंडल के सेवा कार्यों और महापुरुषों के जीवन चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात, विधायक एवं मंचासीन अतिथियों ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए पुरंदर मिश्रा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने अपने वक्तव्य में छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि "कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं और प्रशिक्षण वह माध्यम है जिससे हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचा सकते हैं।" प्रशिक्षण शिविर में मंच का संचालन अश्वनी विश्वकर्मा द्वारा किया गया।

उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से रायपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें विधायक पुरंदर मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संदीप जंघेल,जिला उपाध्यक्ष अकबर अली,महामंत्री गुंजन प्रजापति,प्रदेश प्रवक्ता तौकीर रजा,युवा मोर्चा अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी एवं महामंत्री शंकर साहू जनप्रतिनिधि पार्षद अवतार सिंह बागल, श्वेता विश्वकर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन साहू, चंद्रेश शाह, संतोष साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश पांडे और महिला मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष भारती बागल मंडल महामंत्री रमेश शर्मा, गीता रेड्डी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

खाद की कालाबाजारी रोकने उर्वरक उड़नदस्ता दल का गठन

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार आगामी खरीफ वर्ष 2026 में किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय एवं अमानक उर्वरकों के विक्रय सहित अन्य अवैध कार्यों को रोकने तथा संबंधित व्यक्ति व फर्म के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इसके साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए जिले में उर्वरक कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर 07744-224109 है।

उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि राजनांदगांव विकासखंड उड़नदस्ता दल के नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि डॉ. बीरेन्द्र अनंत, डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखंड उड़नदस्ता दल के नोडल अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी संतलाल देशलहरे, डोंगरगढ़ विकासखंड उड़नदस्ता दल के नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्रीमती संध्या कोचरे को नियुक्त किया गया है। उड़नदस्ता दल द्वारा उर्वरक से संबंधित शिकायतों, गोपनीय सूचना के निवारण एवं अवैध गतिविधियों की तत्काल सूचना प्राप्त होने पर एफसीओ 1985 के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

वाटर एंबुलेंस सेवा 32 गांवों के लिए समय पर मिलेगी मेडिकल सुविधा

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

स्वास्थ्य सुविधा के लिए जंगल, उबड़-खाबड़ व पहाड़ मार्ग से अस्पताल तक पहुंचना डुबानावासियों के लिए चुनौती भरा है, लेकिन कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की पहल ने घंटों का काम मिनटों में कर दिया है। 50 किलोमीटर की दूरी जलमार्ग से अब सिर्फ सात किलोमीटर रह गया है, जिसे वाटर एंबुलेंस से सिर्फ 45 मिनट में पार कर लिया जाएगा और समय पर जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे डुबानावासियों के लिए जल मार्ग एक बड़ी उपलब्धि होगा। जिसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, इसे धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सोचकर डुबानावासियों के लिए जलमार्ग को वरदान साबित कर दिया है।

जिले के दूरस्थ एवं डुबान प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गंगरेल बांध क्षेत्र में वाटर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज डुबान क्षेत्र के विभिन्न गांवों का सघन दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि

डुबान क्षेत्र के ग्रामीणों को अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपचार मिलना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। इस समस्या के निराकरण के लिए शुरू की गई वाटर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से अब ग्रामीणों को त्वरित एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पहले जहां जिला मुख्यालय तक पहुंचने में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं अब जलमार्ग के माध्यम से यह दूरी घटकर लगभग सात किलोमीटर रह जाएगी। वाटर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध होने से डुबान क्षेत्र के ग्राम चिखली, माटेगहन, मोंगरागहन, मोंगरी, उरपुटी, कोड़ेगांव बी, कोड़ेगांव रैय्यत समेत कई गांवों के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा।

माओवाद के अंत के साथ बस्तर क्षेत्र में अब विकास को मिलेगी नई दिशा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव के सुदूर अंचल स्थित ग्राम केजंग पहुंचे और क्षेत्रवासियों को लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के 11 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न ग्राम पंचायतों में सड़क, भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं सड़कों, पुलों, जल संरक्षण के कार्य और सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचल में आवागमन को आसान बनाना, कृषि को मजबूती देना और ग्रामीण जीवनस्तर में सुधार लाना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आम नागरिकों के हित में क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पूर्व में माओवाद से प्रभावित रहा है, किन्तु पूरा छत्तीसगढ़ माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो गया है और अब बस्तर संभाग भयमुक्त होकर विकास की मुख्यधारा में तेजी से

आगे बढ़ेगा और अधिक समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार मिलेगा।

विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किए गए कार्यों में ग्राम पंचायत कुधुर में 1 किमी मुरमीकरण कार्य (मांझानार से साहूपारा प्रतीक घर तक) लागत 19 लाख रुपए, तरईपारा से पंडेला घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए, ग्राम पंचायत कोरमेल के पटेलपारा में सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत जोडेंगा में सांस्कृतिक भवन से कमलू घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पदनार में प्राथमिक शाला भवन से समलू घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पुसपाल में नीचेपारा में कुलधर घर से सुधीर यादव घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए, ग्राम पंचायत मड़ागांव में सांस्कृतिक भवन से पीलाराम घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। ग्राम पंचायत केजंग में घोटुल गुड़ी के पास शेड निर्माण लागत 6 लाख रुपए, ग्राम पंचायत मडानार में स्कूल मुख्य द्वार से पेदेवाई घर तक सीसी सड़क निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए एवं प्राथमिक शाला में शौचालय निर्माण लागत 5 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत बेतबेड़ा में मुख्य मार्ग से ढोलमांदरी सन्नू घर तक मार्ग मुरमीकरण 15.00 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, उपाध्यक्ष टोमेन्द्र ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, कोण्डागांव एसडीएम अजय उरांव, तहसीलदार मनोज रावटे एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

हरित खाद, नीली-हरी शैवाल के उत्पादन तकनीक और उपयोग को गांव-गांव तक पहुंचाएं-शहला निगार

हरित खाद, नीली-हरी शैवाल और जैव उर्वरकों पर दिया जोर, राज्य के 150 से अधिक कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को दिया गया प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ की। उन्होंने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'हरित खाद, नीली-हरी शैवाल एवं जैव उर्वरकों' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी खरीफ सीजन से पहले किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों के प्रति जागरूक करना और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना था।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों की संभावित कमी को देखते हुए हरित खाद, नीली-हरी शैवाल और जैव उर्वरक जैसे विकल्प फसलों की पोषक

आवश्यकताओं का लगभग 50 प्रतिशत तक पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले दो से तीन महीनों में इन तकनीकों के उत्पादन और उपयोग को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए 150 से अधिक कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर उभरती अनिश्चितताओं के बीच छत्तीसगढ़ ने टिकाऊ कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दक्षिण-पूर्व एशिया और विशेषकर ईरान में जारी संघर्ष के कारण पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरक निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल के आयात पर संभावित असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैकल्पिक पोषक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल तेज कर दी है।

तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने मृदा स्वास्थ्य सुधार और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए जैविक एवं पर्यावरण-अनुकूल उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने बताया कि नीली-हरी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर धान की खेती में इसकी उपयोगिता अधिक है। वहीं, हरित खाद से मृदा की संरचना बेहतर होती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को भविष्य की कृषि के लिए अनिवार्य बताया गया।

कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें नीली-हरी शैवाल उत्पादन की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा खरीफ सीजन के लिए इन विकल्पों के व्यापक उपयोग की रणनीति पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन वैकल्पिक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो न केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि किसानों की लागत में कमी और मृदा स्वास्थ्य में सुधार भी सुनिश्चित होगा। कार्यक्रम के अंत में सतत, पर्यावरण-अनुकूल और आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।

सोलह दूनी आठ
नई दृष्टिबिंदु

साप्ताहिक कॉलम

याज्ञवल्क्य मिश्रा

सर फाईट पॉवर्टी एवरी मूवमेंट

सहाफी उत्तर छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में घूम रहा था। वहां के साहब को लेकर हर क्षण ग़रीबी से लड़ने का किस्सा रौशन है। एक एसी का बिल पाँच थानेदार को टिका कर सबसे पेमेंट करा लेना जैसी जुगत अब पुरानी है। साहब ने नया कौतुक किया है। साहब का मानना है कई खेल आदिकाल से खेले जाते हैं, उन्हे संरक्षित और प्रोत्साहित कर खेल खिलाड़ी की बेहतरी के साथ यदि गरीबी से लड़ा जा सके तो इससे बेहतर क्या होगा। वही बेहतर और शानदार कार्यक्रम जारी है। जिले में एक जगह है जो आदिकाल से अक्षवती के लिए पहचानी जाती रही है। जंगल के बीचों बीच यहां अक्षवती खेलने दिगर प्रदेशों से भी शौकीन आते हैं। कुछ लोग जो साहब की नेकनीयती और पावर्टी फाईटिंग स्पिरिट से जलते हैं वो अक्षवती जैसे कान को अच्छे लगने वाले शब्द के बजाय कहते हैं कि जुआ चल रहा है वो भी इंटर स्टेट। छोड़िए इन जलनखोरों की बात क्या ही सुनना। ग़रीबी से लड़ना एक राष्ट्रीय दायित्व है। गरीबी से लड़ाई तो नेशनल लेवल पर जारी है देखिए न नेहरु जी से लेकर मोदीजी तक गरीबी से लड़ रहे हैं, पर ये ग़रीबी जाने क्या संजीवनी के साथ हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। हालाँकि कुछ लोग ये कहते हैं ग़रीबी से लड़ने जैसी बात कहने और करने से अमीरी आती है और सरकार दीनदयाल कृपालु मानी जाती है इसलिए गरीबी को बनाए रखा जाता है और लड़ाई भी लड़ी जाती है। तो एक जिला यदि भी यदि इस राष्ट्रीय दायित्व में गिलहरी योगदान दे रहा है तो बुरा क्या है।

सुशासन सरकार में विकास नाराज

हालिया दिनों टीआई स्तर के अफसरों की लिस्ट निकली। जानकार कहते हैं ये पहली है अभी और निकलेगी। अब निकलें ना निकलें अपनी बला से। अपने राम की नजर टिक गई रायपुर कमिश्नरी से रवाना किए गए साहबों के नाम पर। इनमें अधिकांश ट्रैफि क के थे। सहाफी को ये तो समझ आया कि ये ट्रांसफर यूँ ही नहीं हुए हैं। एक साहब ने सहाफी को यह कहते हुए राज खोला कि किसी को मत बताना। साहब ने बताया कि, ट्रेफि क के बड़े साहब ने सभी थानेदारों को कह दिया था कि किसी की नहीं सुनना है, जो मैं कहूँ सो करो। कार्यवाही में किसी को नहीं बख़्शना है और कार्यवाही होने के पहले किसी को बताना भी नहीं है। अब ट्रेफिक के वो अफसर जो साहब और थानेदार के बीच के थे वो बिदक गए। वो कमिश्नरी के बड़े साहब के पास पहुंच कर दर्द बता आए। फिर आई लिस्ट। लिस्ट में चिन्हाकित दरोगा साहबान के नाम थे। बताते हैं ट्रैफिक के बड़े साहब ने उपर आला अफसरों से आग्रह निवेदन किया कि, काम के लोग चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। साहब जोर गुस्सा थे तो उनका क्रोध इटंरनल व्हाट्सएप ग्रुप पर उमड़ गया। अब लोग उसका स्क्रीन शॉट लेकर छितराए पड़े हैं।

अब तो मजबूरी है

प्रभारी डीजीपी से पूर्णकालिक डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर सरकार का फैसला किसी भी दिन सार्वजनिक हो सकता है। वजह है सर्वोच्च अदालत के कड़े तेवर के साथ इस हफ़्ते होने वाली पेशी। पेशी की तारीख आने के पहले नाम सार्वजनिक कर यूपीएससी को सूचित करना ही होगा। अब यूपीएससी से आए दो नाम अरुण और हिमांशु में से किस पर सरकार टिक लगाती है, यह सरकार के नीति नियंता जाने।

भैया का जज़्बाती होना

मध्य छत्तीसगढ़ में एक सियासती रसूखदार परिवार है। परिवार में बड़े भैया हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके छोटे भैया हैं जो मंत्री के साथ आधा दर्जन से अधिक बार विधायक पद सुशोभित कर चुके हैं। हालाँकि हालिया चुनाव में छोटे भैया एकदम नौसिखिया से हार कर धूल धूसर हो गए हैं। छोटे भैया फिर से जुटे हैं कि अब फिर से मैदान में उतरें, लेकिन उनके बड़े भैया इस कदर जज़्बाती हुए हैं कि जोत का दीपक ही तेल के बजाय पानी से भिगो गए हैं। कांग्रेस भवन में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो भैया ने फेसबुक पर पोस्ट लिख डाला कि कांग्रेस कार्यालय में क्यों कराए ये पाठ। भैया ने लिखा कि कांग्रेस को बीजेपी की ऐसी नक़ल क्यों करना चाहिए। भगत सिंह गांधी नेहरु पढ़ें। हालाँकि वे साथ में यह भी लिख गए कि वे कट्टर सनातनी हैं और उनके गुरु ब्रम्हलीन हो चुके शंकराचार्य जी हैं। अब पोस्ट हो गई वायरल और लोगों ने प्वाइंटेड अर्थ निकाल लिया। इस पोस्ट से और तो कुछ नहीं हुआ लेकिन छोटे भैया को जरुर झटका लग गया क्योंकि पिछला चुनाव वे तुष्टिकरण के आरोप पर ही हारे थे, अब चालीसा पाठ पर पोस्ट ने फिर से वही याद ताजा करा दी। वैसे ये बड़े भैया बबलू भैया शासनकाल में भी जज़्बाती हो लिए थे। बताते हैं जज़्बाती होकर इन्होंने ही बबलू भईया को एडवाइज दी थी क्यों ढाई साल में कुर्सी देना। इसके बाद बबलू भैया सीएम तो रह गए पर कांग्रेस की लुटिया डूब गई।

सिपाही का जलवा

एक सिपाही जी हैं, जिनके जलवा फरोशी के रंगदार क़िस्से हैं। महादेव की गूंज में सिपाही जी का नाम भी खूब गूँजा। ये सिपाही जी राजनांदगाँव में एक बार चर्चा में आ गए। रायपुर के बड़े साहब ने सीधे पत्र जारी कर जाँच के आदेश दे दिए। अब मजाल है कि कोई जाँच की बात कर दे, जाँच की प्रगति पूछना तो अलग ही रह गया है। अफवाह है कि सिपाही साहब की जाँच शुरू हुई लेकिन जैसे जैसे कॉल डिटेल आते गए और उसमें नाम नंबर को अफसर देखते गए तो समझ आया कि भाँग तो पूरे कुएँ के पानी में मिली है। इसलिए जाँच पर फुल स्टाप लगा दिया गया है। बड़े साहब को याद रखना चाहिए सिपाही साहब दुबई रिटर्न है लेकिन ना ईडी ना सीबीआई और ना ईओडब्लू इनका कुछ बिगाड़ पाई है।

गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट

सुशासन बाबू की सरकार अहर्निश सेवा में तत्पर है। अब सेवा किसकी इसे लेकर अलग अलग दावे हैं कुछ दावे आरोप की तरह भी हैं। पर अपन है सरकार के भक्त। सो अपने राम ये मानते हैं कि इस दौर में जहाँ सेवा भावी नहीं मिलता वहाँ यदि पूरी सरकार सेवा में हो तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल मामला ये है कि, सुशासन बाबू की सरकार ने जैसा कि वह हर हफ़्ते करती है इस हफ़्ते भी दिल लूट लिया है। देखिए विकास के मायने क्या होते हैं, मायने होते हैं कि अंकों का आगे बढ़ना। तो अंक आगे बढ़ें हैं। कांग्रेस शासनकाल में अंक था 20। अब अंक है 22। वैसे दो किश्त को जोड़ लें तो चालीस था यहाँ पर अब चवालीस हो गया है। सिस्टम वही है लेकिन देखिए गुड गवर्नेंस कि आँकड़े में वृद्धि हो गई। सुशासन बाबू की सुशासन सरकार के साथ इस सरकार के विकास आँकड़े को कुछ जलनखोर और विरोधी भ्रष्टाचार बताते हुए कह रहे हैं कि यदि यही करना है तो सेंट्रल और स्टेट की एजेंसियों से जेल काहे भिजवा दिए। जैसा कि सहाफी उपर लिख चुका है वह पूरी तरह नख से शिखा तक सरकार पर पूरी आस्था और विश्वास रखता है और दृढ़ता से मानता है कि, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये केवल विकास के आँकड़े हैं। विरोधी और जलनखोर जो जाने कौन सी एजेंसियों की बातें कर भ्रष्टाचार का हवाला दे रहे हैं यह हर बात पूरी तरह झूठ है। सुशासन बाबू की सरकार का हर काम पाक है साफ है याने कि सफेद है बिलकुल चावल की तरह।

चर्चा तो हुई न

सियासत के तंबू ठीक ठाक तने रहने के लिए तीन बंबू चाहिए। ये तीन बंबू हैं 'चर्चा,पर्चा,खर्चा'। महाराष्ट्र की सीमा से लगी एक विधानसभा के विधायक जी का सियासती तंबू ठीक तना हुआ है। एमएलए साहब लोकरंग पर समर्पित कार्यक्रम कराते हैं, सरकार से फंड भी मिल जाता है। याने खर्चा का मैनेजमेंट कंप्लीट है। अब बचा पर्चा और चर्चा। तो उन्होंने पर्चा छपवाया और पर्चा छपते ही चर्चा शुरु हो गई। पर्चे का मतलब है कार्यक्रम का कार्ड। प्रोग्राम में अध्यक्षता समेत महत्वपूर्ण आसंदी में नाम विधायक जी ने विपक्ष के क़द्दावरों के डाल दिए। जबकि परंपरानुरुप माना जा रहा था कि, विधायक जी अपने दल के कद्दावरों को प्रदेश याने रायपुर से बुला लेंगे और कार्ड में उनका नाम होगा। अब इस पर्चे की चर्चा कांग्रेसी भी कर रहे हैं और भाजपाई भी। यूँ एक खबर ये भी है कि कार्ड में नाम चिपकाने के बावजूद बीजेपी के क़द्दावर कार्यक्रम में नहीं गए। अब विधायक जी का बीजेपी प्रेम हिलोर ले रहा हो तो शायद जाना बेहतर होता। बहरहाल विधायक जी ने तीन बंबू सफलता से गाड़े हैं और सियासत का तंबू ठीक हो लिया है। अब कोई आए मत आए, सरकार से फंड आ गया, पर्चा भी छप गया और चर्चा भी खूब हो गई।

अफसेंटी की तनखा

पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक अजब ग़जब हुआ है। हुआ ये है कि उप अभियंता जी पर रेप केस दर्ज हो गया। युवा सब इंजीनियर एफआईआर होते ही नदारद हो लिया। महीनों यह तब तक ग़ायब रहा जब तक कि जमानत नहीं हो गई। इसके पहले डिपाटमेंट के साहब ने सब इंजीनियर को ग़ैर हाजिर पर कई नोटिस भेजे। जादू तब हुआ जब अचानक से सब थम गया और युवा छबीला सब इंजीनियर ज्वाईन कर गया। अब महीनों की ग़ैर हाज़िरी पर तनखा भी बन रही है।

मैनेजमेंट

मैनेज करना मैनेज होना और मैनेज कर लेना तीनों अलग अलग हैं पर तीनों के लिए कमाल का गुण होना चाहिए। सरहदी इलाक़े का क़िस्सा है। रेप केस में एक साहब के खिलाफ चालान पेश किया गया। वर्दी वाले साहबों ने वही रिकॉर्ड गोल कर दिए जिससे कि अपराध की अकाट्य पुष्टि होती। मामले की शिकायत रेंज के सबसे बड़े साहब तक गई। साहब ने कड़ा पत्र जारी कर निर्देश दिया कि महिला विवेचक और प्रभारी से स्पष्टीकरण लिया जाए और फौरन से पेश्तर जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो कोर्ट में जमा किए जाएँ। लेकिन वही शब्द मैनेजमेंट। बड़े साहब की चिट्ठी आई और गई। चालान में ठेंगे से कुछ जमा नहीं हुआ। अब कौन कौन मैनेज हुआ कैसे मैनेज हुआ और किसने मैनेज किया यह पब्लिक डोमेन में थोड़े ही आता है।

लोकतंत्र सबका है

लोकतंत्र सबका होता है। अकेले किसी पॉलिटिकल पार्टी या वर्कर का तो होता नहीं न। सबका मतलब सबका। एक नगर निगम में नेताजी लोगों को लगा कि लोकतंत्र है और उन्ही का है। बीजेपी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दिया और इसके बाद गोवा के टूर पर निकल गए। लेकिन वही बात लोकतंत्र में अधिकार संपर्क संवाद तो साहब का भी है। पक्ष विपक्ष का दल गोवा टूर से लौट आया पर साहब जस के तस कुर्सी पर विराजमान हैं। इत्मिनान से चेक काट रहे हैं। सनद रहे कि हटाने के प्रस्ताव के बाद जिस गोवा यात्रा पर पक्ष विपक्ष रवाना हुआ था, साहब को उसका बिल भी पास करना है। इधर राज्य और निगम में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताजी सब परेशान हैं कि इतना तीन तूफान किए लेकिन गुड गवर्नेंस गवर्मेंट ने कुछ किया ही नहीं।

व्हाट्सएप पर ये मैसेज

व्हाट्सएप भी अपने आप में विश्वविद्यालय है। कुछ भी कभी भी कहीं से भी ज्ञान आता है और भरपूर वितरित भी होता है। रफ्तार इतनी तेज होती है कि सच झूठ का जब तक पता करें तब तक झूठ डिजिटल वर्ल्ड का फेरा कर लेता है। अब ऐसा ही एक वायरल होता मैसेज है। यह मैसेज डिपार्टमेंट और मिनिस्टर के नामोल्लेख के साथ जारी है। मैसेज बता रहा है कि इस विभाग में जो रोटेशन सिस्टम है वही नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीफोन से जो दर बताई जा रही है वह इतनी ऊँची है कि जल्दी कोई फॉर्म भर नहीं रहा है। व्हाट्सएप का यह वायरल मैसेज दावा करता है कि कोई ओएसडी हैं और ऐसे जलवेदार हैं कि सब कुछ उन्हीं के हवाले है। वर्कलोड ज्यादा है तो ओएसडी साहब का अपना एक पीए है। फोन पर ऑक्शन रेट या कि रिचार्ज रेट यही पीए साहब बताते हैं। इस वायरल मैसेज में यह दर्द भी है कि बताईए कोई एचओडी को पूछ नहीं रहा है ओएसडी सब फसल खा दे रहे हैं। सहाफी ने इसका ओर छोर पता लगाने की कोशिश की तो जिससे पूछा वो इस्माइली देकर निकल लिया। पर एक साहब ठहरे और उन्होंने कहा पत्रकार जी, इस डिपाटमेंट में कौन कहां रहे कैसे रहे इसे लेकर रुचि और इंटरफेयर केवल भारसाधक मंत्री का ही नहीं कहीं और से भी है और बहुत जोर से है, इसलिए मैसेज तो पढ़ो लेकिन जो नहीं लिखा उसे भी पढ़ो। अपने राम को कहां समझ आना था कुछ, तो सहाफी ये जा वो जा।

चंद्रनाहु कुर्मी समाज ने खेती-किसानी से लेकर शिक्षा और सेवा तक हर मोर्चे पर प्रदेश को किया है सशक्त -विजय शर्मा

शिवाजी महाराज के आदर्श हमें सिखाते हैं कि संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं - ललित चंद्राकर

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जामगांव (एम) में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज, दुर्ग राज का 56वाँ वार्षिक अधिवेशन आज गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए। अतिथियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके राष्ट्र-निर्माण में योगदान का स्मरण किया तथा समाज गंगा को प्रणाम कर कृषि, शिक्षा, रोजगार एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजजनों को सम्मानित किया।

अपने संबोधन में प्रदेश के यशस्वी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें स्वराज, स्वाभिमान और सुशासन की प्रेरणा देता है। चंद्रनाहु कुर्मी समाज ने खेती-किसानी से लेकर शिक्षा और सेवा तक हर मोर्चे पर प्रदेश को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए राज्य सरकार गाँव, गरीब और किसान के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 3100/क्विंटल पर धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मैं समाज के युवाओं का आह्वान करता हूँ—शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के माध्यम से आगे आएँ, सरकार हर कदम पर आपके साथ है।

अपने संबोधन में विधायक विधायक ललित चंद्राकर के कहा चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज, दुर्ग राज की एकता, अनुशासन और सेवा-भावना अनुकरणीय है। शिवाजी महाराज के आदर्श हमें सिखाते हैं कि संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हमारे समाज के अन्नदाता, शिक्षक, कलाकार और उद्यमी—सभी ने अपनी मेहनत से दुर्ग ग्रामीण का गौरव बढ़ाया है। आज सम्मानित हुए प्रतिभाओं को बधाई—आपकी उपलब्धियाँ अगली पीढ़ी को दिशा देंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम बुनियादी सुविधाओं—सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा—के विस्तार के साथ-साथ सामाजिक समरसता को और मजबूत करेंगे। समाज भवन, शिक्षा प्रोत्साहन और कौशल केंद्रों के लिए हरसंभव सहयोग मेरा संकल्प है।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से केंद्रीय चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज अध्यक्ष दिनेश चंद्राकर, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष अश्वनी चंद्राकर, केंद्रीय महासचिव कुंदन चंद्राकर, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी चंद्रवंशी, संगठन मंत्री होरीलाल चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षा चंद्राकर, अध्यक्षता प्रदीप चंद्राकर, उपाध्यक्ष चंद्रकिशोर चंद्राकर सचिव शिव चंद्राकर, रोहित चंद्राकर, राजेश चंद्राकर, जामगांव (एम) अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर, छतर सिंह चंद्राकर, भूषण चंद्राकर, अशोक चंद्राकर, तुंगजध्वज चंद्राकर, अवीक चंद्राकर, उपकार चंद्राकर, तोरण चंद्राकर, लवकुश चंद्राकर, श्रीमती नीता चंद्राकर, श्रीमती सरला चंद्राकर, केके राजू चंद्राकर, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, हर्षी चंद्राकर, सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

धारदार हथियार से हमला कर भय फैलाने वाला आरोपी को सुपेला पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शनिवार की रात्रि प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने मित्रों के साथ नेहरू नगर क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। रात्रि में एक अज्ञात युवक ने सिगरेट मांगा इस पर मना करने पर गाली-गलौज की गई और बाद में पुनः आकर विवाद करते हुए धारदार हथियार से प्रार्थी के बाएं पसली में तथा उसके साथी के दाहिने हाथ में चोट पहुंचाई गई। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

सुपेला पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 489/2026 धारा 296, 115(2), 351(3) इटर एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की पहचान कर तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। आरोपी का नाम आलोक राम टेके, उम्र 19 वर्ष, निवासी अटल आवास, नेहरू नगर, सुपेला, दुर्ग बताया गया है। आरोपी के पास से एक धारदार हथियार बरामद किया गया हैं।

इस कार्रवाई में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, सउनि राजीव उवर्सा, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूयर्वंशी, सुरेन्द्र पटेल की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ललित बने जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

ललित कुमरे को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में महामंत्री नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ललित कुमरे एक सुलझे हुए राजनीतिक नेता है उन्हें सामाजिक के साथ-साथ राजनीति की भी अच्छी जानकारी है वह मिलनसार और मृदु भाषी है।

उनकी राजनीतिक शुरुआत स्वर्गीय उदय मुदलियार के साथ हुई और तब से वे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं वे तीन बार युवक कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रहे फिर उन्हें किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया जिस पर उन्होंने संगठन के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया इस बार भी उनकी सक्रियता को देखते हुए संगठन ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है वे अपना राजनीतिक गुरु जितेंद्र मुदलियार को मानते हैं निसंदेह ही पार्टी में उनकी नई जिम्मेदारी में वह खरा उतरेंगे।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100